

03 पुरा अप मैन रोहतास चौधरी के सम्मान में खानपुर में स्वागत समारोह

06 एडवेंचर स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर में नौकरी के अवसर और करियर विकल्प

08 सरायकेला में भव्य अन्नपूर्णा मंदिर की प्रतिष्ठा पुरी के पंडितों ने की

नमो भारत ट्रेन को लेकर बड़ा अपडेट मात्र 40 मिनट में पूरा होगा 2 घंटे का सफर

परिवहन विशेष न्यूज

न्यू अशोक नगर और मेरठ साउथ के बीच नमो भारत ट्रेन जल्द फर्राटा भरेगी। अब तक सड़क मार्ग से दिल्ली से मेरठ के सफर में करीब दो घंटे का वक्त लगता है लेकिन जल्द ही यह सफर मात्र 40 से 45 मिनट में पूरा हो सकेगा। ताजा अपडेट है कि दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ RRTS कॉरिडोर पर ट्रायल रन तेजी से आगे बढ़ रहा है। आनंद विहार और न्यू अशोक नगर स्टेशनों के जल्द ही खुलने की उम्मीद है। चालू होने के बाद, RRTS कॉरिडोर की लंबाई 42 किमी से बढ़कर 54 किमी हो जाएगी, जिससे नमो भारत ट्रेन सेवाएं न्यू अशोक नगर और मेरठ साउथ के बीच केवल 40-45 मिनट में त्वरित यात्रा प्रदान करने में सक्षम होंगी।

नई दिल्ली। साहिबाबाद और न्यू अशोक नगर के बीच दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ RRTS कॉरिडोर पर ट्रायल रन तेजी से आगे बढ़ रहा है। आनंद विहार और न्यू अशोक नगर स्टेशनों के जल्द ही खुलने की उम्मीद है। चालू होने के बाद, RRTS कॉरिडोर की लंबाई 42 किमी से बढ़कर 54 किमी हो जाएगी, जिससे नमो भारत ट्रेन सेवाएं न्यू अशोक नगर और मेरठ साउथ के बीच केवल 40-45 मिनट में त्वरित यात्रा प्रदान करने में सक्षम होंगी।

नोएडा के पास स्थित न्यू अशोक नगर स्टेशन दिल्ली और नोएडा दोनों के यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में डिजाइन किया गया यह RRTS स्टेशन दिल्ली मेट्रो

के ब्लू लाइन से जुड़ेगा। न्यू अशोक नगर RRTS स्टेशन को अशोक नगर मेट्रो स्टेशन से जोड़ने के लिए 90 मीटर का फुट ओवरब्रिज (FOB) निर्माणाधीन है।

यह कनेक्शन यात्रियों को परिवहन के दो साधनों के बीच निर्बाध रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति देगा, जिससे भीड़भाड़ कम होगी और यात्रा आसान होगी, खासकर महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों या सामान वाले परिवारों के लिए। इसके अतिरिक्त, 600 वाहनों की संयुक्त क्षमता वाले दो पार्किंग क्षेत्र प्रदान किए जाएंगे, जिनमें कार, मोटरसाइकिल और साइकिल के लिए स्थान शामिल हैं।

मेट्रो से कनेक्टिविटी भी होगी आसान

पार्किंग के पहले 10 मिनट नि:शुल्क होंगे, जिससे रफिक एंड डॉपर सेवा का उपयोग करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। इस बीच, भूमिगत आनंद विहार RRTS स्टेशन कॉरिडोर पर सबसे व्यस्त पारगमन केंद्रों में से एक बनने के लिए तैयार है। यह दो मेट्रो लाइनों (नीली और गुलाबी), आनंद विहार रेलवे स्टेशन और दो ISBT से जुड़ा होगा।

एक दिल्ली की ओर और दूसरा उत्तर प्रदेश के कौशांबी की ओर। इससे प्रतिदिन

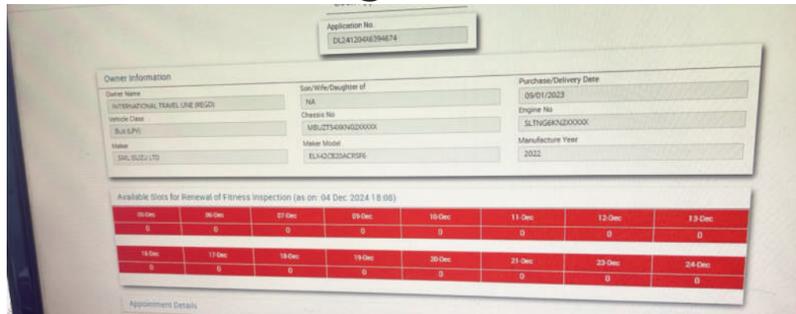


उच्च पैदल यातायात सुनिश्चित होगा। NCRTC RRTS स्टेशन को इन परिवहन साधनों के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत करने के लिए काम कर रहा है, जिससे यह मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए एक मॉडल बन जाएगा। पहुंच को और बेहतर बनाने के लिए, गाजीपुर नाले पर तीन नए पुल बनाए गए हैं।

एक वाहन प्रवेश के लिए, एक वाहन निकास के लिए और एक पैदल यात्रियों की आवाजाही के लिए, जिससे स्टेशन तक सुगम पहुंच सुनिश्चित होगी। स्टेशन का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है, तथा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

2025 तक चालू होने की उम्मीद है, जिससे मेरठ और नोएडा के बीच यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार होगा। पूरा आरआरटीएस कॉरिडोर, जिसके जून 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है, दिल्ली के सराय काले खां और मेरठ के मोदीपुरम के बीच यात्रा का समय एक घंटे से भी कम कर देगा।

बसों की फिटनेस झूलझुली फिटनेस सेंटर में काफी दिनों से रूकी होने की शिकायत के लिए मुख्यमंत्री को लिखा पत्र



परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन ने बसों की फिटनेस झूलझुली फिटनेस सेंटर में काफी दिनों से रूकी होने की शिकायत के लिए एक पत्र दिल्ली की मुख्यमंत्री को लिखा।

ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट का कहना है कि दिल्ली के झूलझुली फिटनेस सेंटर में बसों की फिटनेस के लिए 20 से 25 दिनों की अपॉइंटमेंट मिल रही है। जिसके कारण लगभग 500 बसें बगैर फिटनेस के कारण पार्किंग में खड़ी हैं।

संजय सम्राट का कहना है कि वास्तव में दिल्ली सरकार और इनका परिवहन विभाग काफी समय से दिल्ली की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीयों को बंद कर रहा है।

उन जमीनों का ये क्या करेगे इसका जवाब अभी ये नहीं दे रहे हैं इसी तरह ये बुराई फिटनेस सेंटर को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जमीन करोड़ों रुपये की हैं धीरे धीरे ये सारी छोटी गाड़ियों को फिटनेस के लिए झूलझुली फिटनेस सेंटर भेज रहे हैं जिसकी वजह से वहाँ फिटनेस के लिए काफी संख्या में गाड़ियाँ जा रही हैं और फिटनेस कराने के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है अगर मिल

भी रही है तो 20 से 25 दिन बाद की।

इस बारे में ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन अपने प्रतिनिधि मण्डल के साथ 2 बार स्पेशल कमिश्नर श्री संजीव मिश्र जी से भी मिले हैं।

लेकिन कमिश्नर साहब ने अभी तक अस्वास्थ्य ही दिया है। अभी तक बस वालों का समाधान नहीं हुआ है ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा है कि अगर हमारी बसों की फिटनेस जल्दी नहीं की गई तो हम दिल्ली की मुख्यमंत्री को खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठेंगे। क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री ही ट्रांसपोर्ट मंत्रालय देख रही हैं।

आश्रम से नोएडा रूट पर लगा भयंकर जाम, गाड़ियों की लंबी कतार; यात्री परेशान



आश्रम से डीएनडी होते हुए नोएडा जाने वाला मार्ग बुधवार शाम भीषण जाम की चपेट में रहा। सड़क धंसने और ट्रक खराब होने के कारण घंटों तक जाम लगा रहा। जाम बढ़ते हुए सराय काले खां तक पहुंच गया और बारापुला प्लाईऑवर पर भी भीषण जाम लगा गया। इस कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

दक्षिणी दिल्ली। आश्रम से डीएनडी होते हुए नोएडा जाने वाला मार्ग बुधवार शाम भीषण जाम की चपेट में रहा। भीषण जाम के चलते नोएडा जाने वाले और नोएडा से आने वालों को घंटों परेशान होने पड़ा। आश्रम प्लाईऑवर के पास सड़क धंस गई थी।

दुर्घटना से बचाव के लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे, इसकी वजह से सड़क संकरी हो गई, जो जाम की वजह बनी। दूसरी ओर आश्रम से नोएडा जाने वाले मार्ग पर ट्रक

खराब होने से जाम लगा रहा। देर शाम तक जाम बढ़ते हुए सराय काले खां तक पहुंच गया। इसके चलते बारापुला प्लाईऑवर पर भी भीषण जाम लगा रहा।

आश्रम से डीएनडी होते हुए नोएडा जाने व आने वाले मार्ग पर लगा जाम, जाम का मुख्य कारण आश्रम प्लाईऑवर के नीचे सड़क धंसना, वहीं आश्रम से नोएडा जाने वाले मार्ग पर ट्रक खराब होने के कारण पीक आवर में लगा भीषण जाम।

पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेस 1 में ए व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। 4 नवंबर बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जगह-जगह ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं उसी कड़ी में आज मयूर विहार फेस-1 मेट्रो स्टेशन के पास मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के करकमलों से ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का भव्य उद्घाटन हुआ।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि हमारे क्षेत्र के समग्र विकास का प्रतीक भी है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इसे प्रेरित करने वाले सभी क्षेत्रवासियों का हृदय से आभार व्यक्त किया यह कहना है मयूर विहार की निगम पार्षद बीना बाल गुहर् का।



वाहनों की पार्किंग के संकट से जूझते शहर

यह जरूरी नहीं है कि अच्छा सार्वजनिक परिवहन यातायात की भीड़ को काफी कम कर दे। भीड़भाड़ की स्थिति में सुधार करने के लिए, शहरों को निजी कारों के स्वामित्व और उपयोग के कार्यात्मक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक मूल्यों को लक्षित करने वाली गतिविधियों के साथ ही अपनी सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को बेहतर बनाने के प्रयासों को मिलाकर काम करना होगा। वाहनों की भीड़ और अपर्याप्त पार्किंग सुविधाएँ भारत के बड़े और महानगरीय शहरों के लिए लगातार बड़ी हो रही चुनौतियाँ हैं, जिनकी वजह से गतिशीलता गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। संवैधानिक आदेशों की वजह से सीमित होने के बावजूद, कई भारतीय शहर पार्किंग नीतियों के माध्यम से इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें विनियमन, प्रबंधन के एक उपकरण के रूप में मूल्य निर्धारण, नई तकनीक और सड़क से इतर (ऑफ-स्ट्रीट) पार्किंग प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

-डॉ सत्यवान सौरभ

भारत में वाहन पार्किंग की समस्या एक महत्वपूर्ण शहरी चुनौती है, जो न केवल यातायात के प्रवाह को प्रभावित करती है, बल्कि शहरी जीवन के मूल ढांचे को भी प्रभावित करती है। यह समस्या, तेजी से बढ़ते शहरीकरण, बढ़ते वाहन स्वामित्व और पुरानी शहरी नियोजन के संयोजन से उत्पन्न होती है, जो महानगरीय क्षेत्रों में यातायात प्रबंधन, शहरी नियोजन और जीवन की गुणवत्ता के लिए एक जटिल दुविधा पैदा करती है। शहरों के विस्तार और कार स्वामित्व के अधिक सुलभ



होने के साथ, भारतीय शहरी केन्द्रों को वाहनों की बढ़ती संख्या को समायोजित करने में संघर्ष करना पड़ रहा है। पर्याप्त पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और आज के समय में वाहनों की संख्या के हिसाब से शहरों को डिजाइन न किए जाने के कारण बड़े पैमाने पर अवैध पार्किंग होती है। इससे न केवल सड़कें जाम होती हैं, बल्कि पैदल चलने वालों के लिए बनी जगह भी कम पड़ जाती है। कई भारतीय शहरों की स्थापना प्राचीन या औपनिवेशिक काल में हुई थी, लेकिन उनकी योजना आधुनिक यातायात की मांग को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई थी। संकरी गलियाँ और मिश्रित भूमि उपयोग के कारण पार्किंग एरिया और चलते वाहनों के भार से दबाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, पार्किंग नियमों का ढीला-ढाला क्रियान्वयन तथा गैर-अनुपालन के प्रति सांस्कृतिक प्रवृत्ति स्थिति को और बिगाड़ देती है, जिससे शहरी स्थान अव्यवस्थित हो जाते हैं।

पार्किंग की समस्या का सीधा परिणाम गंभीर यातायात भीड़ है, जिसके कारण यात्रा का समय बढ़ जाता है, प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, तथा शहरी जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आती है। पैदल चलने वालों को विशेष रूप से परेशानी होती है, क्योंकि पार्किंग एरिया और चलते वाहनों के भार से दबाव पड़ता है और यह भारत के लिए महत्वपूर्ण है। सभी पांच शहरों की पार्किंग नीतियाँ कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर सहमत होती दिखती हैं। वे इस बात पर एकमत हैं कि पार्किंग मुफ्त नहीं हो सकती और जहाँ भी सार्वजनिक स्थान का उपयोग किया जाता है, वहाँ शुल्क लिया जाना चाहिए क्योंकि 'मुफ्त पार्किंग' की अवधारणा टिकाऊ नहीं है।

दृष्टि से, पार्किंग की कमी स्थानीय व्यवसायों को प्रभावित करती है, क्योंकि भीड़भाड़ वाली सड़कें ग्राहकों को आकर्षित नहीं करती हैं। पार्किंग स्थल की उच्च मांग से अचल संपत्ति की लागत भी बढ़ जाती है, जिससे हरित स्थलों की क्रीम पर पार्किंग अवसंरचना के विकास को बढ़ावा मिलने से शहरी विस्तार और पर्यावरण क्षरण को बढ़ावा मिलता है। भारत में मोटर वाहनों से सम्बंधित मामले केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालांकि भारत के शहरों के लिए वाहनों की बढ़ती भीड़ एक उभरती हुई समस्या है, लेकिन ऑटोमोबाइल उद्योग पर प्रतिबंध लगने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इसकी आर्थिक और रोजगार देने की क्षमता काफी ठीक है और यह भारत के लिए महत्वपूर्ण है। सभी पांच शहरों की पार्किंग नीतियाँ कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर सहमत होती दिखती हैं। वे इस बात पर एकमत हैं कि पार्किंग मुफ्त नहीं हो सकती और जहाँ भी सार्वजनिक स्थान का उपयोग किया जाता है, वहाँ शुल्क लिया जाना चाहिए क्योंकि 'मुफ्त पार्किंग' की अवधारणा टिकाऊ नहीं है।

सेंसर और स्वचालित लाइसेंस प्लेट पहचान जैसी तकनीक का उपयोग करके पार्किंग प्रबंधन को सुलभ और कुशल किया जा सकता है। इसके अलावा, भूमि मूल्य और भीड़भाड़ के आधार पर पार्किंग शुल्क को समायोजित करके भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अनावश्यक वाहन उपयोग को हतोत्साहित किया जा सकता है। बुनियादी ढांचे के समाधान के अलावा, सार्वजनिक परिवहन और टिकाऊ शहरी गतिशीलता प्रथाओं को बढ़ावा देने से पार्किंग दबाव कम हो सकता है। सार्वजनिक परिवहन, साइकिल और पैदल चलने के उपयोग को प्रोत्साहित करने से निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो सकती है, जिससे पार्किंग स्थलों की मांग कम हो सकती है।

यह जरूरी नहीं है कि अच्छे सार्वजनिक परिवहन यातायात की भीड़ को काफी कम कर दे। भीड़भाड़ की स्थिति में सुधार करने के लिए, शहरों को निजी कारों के स्वामित्व और उपयोग के कार्यात्मक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक मूल्यों को लक्षित करने वाली गतिविधियों के साथ ही अपनी सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को बेहतर बनाने के प्रयासों को मिलाकर काम करना होगा।

भारत में वाहन पार्किंग की समस्या एक जटिल मुद्दा है जिसके लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें शहरी नियोजन, नीति सुधार, तकनीकी नवाचार और सांस्कृतिक परिवर्तन शामिल हैं। इस चुनौती से सीधे निपटकर, भारत अपनी शहरी गतिशीलता को बढ़ा सकता है, अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है और टिकाऊ शहरी विकास के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है। आगे का रास्ता सरकार, निजी क्षेत्र और जनता के बीच बेहतर शहरी स्थानों की पुनर्कल्पना और पुनर्निर्माण के लिए सहयोगात्मक प्रयासों में निहित है।

स्मार्टफोन के बगैर नहीं रह सकते हैं 71 प्रतिशत बच्चे, माता-पिता भी कम नहीं; रिसर्च में हुए चौंकाने वाले खुलासे



एक सर्वे में पता चला कि माता-पिता और बच्चों के मजबूत रिश्तों के निर्माण में स्मार्टफोन बाधक है। सर्वे के खुलासे से यह सवाल उठने लगा है कि स्मार्टफोन की इस दुनिया में परिवार कैसे एक-दूसरे से सार्थक रिश्ते कायम कर सकता है। बच्चों में स्मार्टफोन की बुरी लत को देखते हुए ही आस्ट्रेलिया में 16 साल तक के बच्चों पर इंटरनेट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है।

नई दिल्ली। देश के 76 प्रतिशत बच्चे तो 84 प्रतिशत अभिभावक एक-दूसरे के साथ अधिक समय व्यतीत करना चाहते हैं, लेकिन स्मार्टफोन और सोशल मीडिया एप उन्हें ऐसा करने से रोक रहे हैं। तभी 94 प्रतिशत बच्चे चाहते हैं कि उनके माता-पिता के स्मार्टफोन में कॉलिंग, मैसेजिंग और कैमरा जैसे सिर्फ तीन फीचर होने चाहिए।

स्मार्टफोन की आदत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं

बच्चे नहीं चाहते हैं कि माता-पिता के स्मार्टफोन में सोशल मीडिया, इंटरनेटमेंट और गेमिंग एप की सुविधा हो। दूसरी तरफ 75 प्रतिशत अभिभावक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनके बच्चे स्मार्टफोन की लत की वजह से परिवार के साथ सार्थक रिश्ते नहीं बना पा रहे हैं। परंतु बच्चे और अभिभावक दोनों ही स्मार्टफोन की आदत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं।

फोन पर घंटों बिताते हैं अभिभावक और बच्चे

स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो और साइबर मीडिया रिसर्च की तरफ से अभिभावक-बच्चों के रिश्तों पर स्मार्टफोन का असर संबंधी अध्ययन में यह खुलासा हुआ है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, अभिभावक रोजाना औसतन पांच घंटे से अधिक तो बच्चे चार घंटे स्मार्टफोन पर अपना समय व्यतीत करते हैं। दोनों ही इनमें से अधिकतर समय सोशल मीडिया और इंटरनेटमेंट एप पर बिताते हैं।

स्मार्टफोन की बुरी लत, बच्चों ने कहा- नहीं छोड़ सकते

76 प्रतिशत अभिभावक तो 71 प्रतिशत बच्चों ने सर्वे के दौरान यह माना कि वे स्मार्टफोन के बगैर नहीं रह सकते हैं। 64 प्रतिशत बच्चे मानते हैं कि उन्हें स्मार्टफोन की बुरी लत लग चुकी है। 160 प्रतिशत से अधिक बच्चों ने बताया कि अगर उनके दोस्त सोशल मीडिया एप से हट जाए तो वे भी सोशल मीडिया एप के इस्तेमाल को छोड़ सकते हैं।

स्मार्टफोन से रिश्तों में दारार की संभावना बढ़ रही

तीन में एक बच्चों ने यहां तक कहा कि इन सोशल मीडिया एप का आविष्कार ही नहीं होना चाहिए था। वीवो ईडिया के कॉरपोरेट स्ट्रेटजी हेड गीतज चन्ना कहते हैं कि टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल सकारात्मक बदलाव और जिंदगी को आसान बनाने के लिए होना चाहिए, लेकिन स्मार्टफोन वास्तविक जीवन के रिश्तों में रूकावट बन सकता है।

अमेरिका के 100% टैरिफ पर क्या है भारत का प्लान? चीन से बाहर मैनुफैक्चरिंग का विकल्प तलाश रही कई कंपनियां

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वस देशों को धमकी दी कि अगर वे डॉलर की जगह किसी दूसरी करेंसी को सपोर्ट करेंगे तो अमेरिका उन पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा। ट्रंप की इस धमकी के बाद भारत चीन और कनाडा समेत कई देशों ने इसपर एतराज जताया। वहीं रिसर्च इंस्टीट्यूट जीटीआरआई ने डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी को अवास्तविक बताया।



अफ्रीकी और एशियाई देशों को इसके प्रभावों के प्रति 'सबसे अधिक' संवेदनशील बताया गया है।

नई दिल्ली। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि भारत को चीन प्लस वन रणनीति अपनाते हैं अब तक सीमित सफलता मिली है। ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट में नीति आयोग ने कहा कि इस नीति का अब तक वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया को बड़ा फायदा मिला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सस्ता श्रम, सरल कर कानून, कम शुल्क और मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर करने में तेजी जैसे कारकों से इन देशों को अपनी निर्यात हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिली।

तलाशने होंगे मैनुफैक्चरिंग के विकल्प

अमेरिका ने चीन की वृद्धि और तकनीकी प्रगति पर होने वाले खर्च को सीमित करने के लिए चीनी वस्तुओं पर सख्त निर्यात नियंत्रण और उच्च शुल्क लागू किए हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बढ़ा बदलाव आया और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को चीन से बाहर मैनुफैक्चरिंग का विकल्प तलाशना पड़ा।

मैनुफैक्चरिंग क्षमताओं को बढ़ाने का अवसर भारत को उन कंपनियों के लिए एक आकर्षक गंतव्य

के रूप में देखा जाता है जो अपना मैनुफैक्चरिंग केंद्र चीन से बाहर स्थानांतरित करना चाहती हैं। यह बदलाव देश को घरेलू खासतौर पर उच्च तकनीक उद्योगों में अपनी मैनुफैक्चरिंग क्षमताओं को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। हालांकि, भारत को अब तक 'चीन प्लस वन रणनीति' अपनाते हैं सीमित सफलता मिली है।

उभरते बाजारों में संभावनाएं तलाशने के अवसर

हाल के वर्षों में श्रम आधारित क्षेत्रों के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी घटी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन कई प्रमुख उत्पाद श्रेणियों में मुख्य प्रतिस्पर्धी है, जिससे भारत के लिए इन उत्पादों में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे विकसित बाजारों में शीर्ष उत्पाद श्रेणियों में मजबूत पकड़ बना ली है, लेकिन उभरते बाजारों में संभावनाएं तलाशने के लिए भी अवसर हैं।

ईयू के सीबीएएम से प्रभावित होंगे भारतीय उद्योग

यूरोपीय संघ (ईयू) के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) का आकलन करने वाले कई अध्ययनों में

अफ्रीकी और एशियाई देशों को इसके प्रभावों के प्रति 'सबसे अधिक' संवेदनशील बताया गया है। सीबीएएम का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को रोकना है और यह जनवरी 2026 से सीमेंट, लोहा और इस्पात, एल्युमीनियम, उर्वरक, बिजली और हाइड्रोजन जैसे उच्च जोखिम वाले आयातों पर लागू होगा।

भारतीय उत्पादों की मांग कम

ईयू को भारत के कुल निर्यात में लोहा और इस्पात उद्योग की 23.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है। सीबीएएम लागू होने से भारतीय कंपनियों पर 20-35 प्रतिशत टैरिफ लग सकता है। इससे लागत बढ़ सकती है, प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है और ईयू के बाजार में भारतीय उत्पादों की मांग कम हो सकती है। ईयू भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2023-24 में भारत के कुल निर्यात में ईयू की करीब 17.4 प्रतिशत (76 अरब डॉलर) हिस्सेदारी रही है।

ट्रंप के उच्च आयात शुल्क के भारत को मिलेगा लाभ

रिपोर्ट जारी करने के बाद नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने बुधवार को कहा कि अमेरिका ने निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चीन और अन्य कारोबारी भागीदारों पर उच्च आयात शुल्क लगाने से भारत को निर्यात के मोर्चे पर लाभ मिलेगा। नीति आयोग के सीईओ ने घरेलू उद्योगों से इस अवसर का लाभ उठाने के लिए खुद को तैयार रहने के लिए भी कहा। पिछले वित्त वर्ष में भारत ने अमेरिका को 77.51 अरब डॉलर का निर्यात किया। इस दौरान भारत का अमेरिका से आयात 42.2 अरब डॉलर रहा है। भारत के आइटी निर्यात वस्तुओं में अमेरिका की 70 प्रतिशत हिस्सेदारी रही है।

सर्दियों में घी का सेवन: 10 बेहतरीन फायदे जो आपको जानने चाहिए

इशिका मुख्य रिपोर्टर रांची झारखंड न्यूज परिवहन विशेष

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही धी को अपनी डाइट में शामिल करने के कई स्वास्थ्य लाभ सामने आते हैं। घी, जो भारतीय खानपान में प्रमुख स्थान रखता है, न सिर्फ स्वाद में अद्भुत है, बल्कि सर्दियों में शरीर को गर्म और तंदुरुस्त बनाए रखने में मदद करता है। यह स्वास्थ्य के लिए आवश्यक वसा, विटामिन और ऊर्जा का एक बेहतरीन स्रोत है।

घी के 10 स्वास्थ्य लाभ

- 1. इम्युनिटी बढ़ाए:** घी में मौजूद फैटी एसिड शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं, जिससे सर्दियों में बीमारियों से बचाव होता है।
- 2. शरीर को गर्म रखे:** घी का सेवन शरीर के अंदर गर्मी पैदा करता है, जो ठंड के मौसम में बेहद जरूरी है।
- 3. पाचन सुधाराता है:** घी पाचन एंजाइमों को सक्रिय करता है और आंतों को चिकना बनाता है, जिससे पेट की समस्याएं दूर होती हैं।
- 4. त्वचा को पोषण दे:**



सर्दियों में घी खाने के फायदे

घी में मौजूद विटामिन और वसा त्वचा को मॉइस्चराइज करते हैं, जिससे सर्दियों में रूखी त्वचा की समस्या कम होती है।

आवश्यक है।

- 6. ऊर्जा का स्रोत:** घी में मौजूद मीडियम-चेन ट्राइग्लिसराइड्स (MCTs) तेजी से ऊर्जा प्रदान करते हैं और आपको पूरे दिन सक्रिय रखते हैं।
- 7. दिमाग के लिए फायदेमंद:** घी में मौजूद स्वस्थ वसा मस्तिष्क के कार्य को बेहतर बनाती है और

याददास्त को मजबूत करती है।

- 8. जोड़ों के दर्द में राहत:** घी के एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण सर्दियों में जोड़ों के दर्द और जकड़न को कम करने में मदद करते हैं।
- 9. वजन घटाने में मददगार:** सीमित मात्रा में घी का सेवन भूख को नियंत्रित करता है और फैट बर्न करने में मदद करता है।

सर्दी ने दी दस्तक, शुरू हुआ शाल वितरण



स्वतंत्र सिंह भुल्लर

नई दिल्ली। यदि हम खुशीहाल जीवन बिताना चाहते हैं तो पहले खुशियां देनी होंगी तभी हमारे मन को शांति और दुआएं मिलेंगी। खुशियों का खजाना ट्रस्ट हमेशा कमजोर वर्ग का ध्यान रखते हुए मौसम अनुसार वस्त्र वितरण, मौके अनुसार भोजन वितरण, पढ़ाई के लिए स्टेशनरी, त्योहारों पर मिठाई बांटना, उनकी दिनचर्या में पूरी तरह समाया हुआ है।

दुमा गर्ग ने बच्चे बड़े सभी को टॉफी चॉकलेट्स आदि बांट कर उनकी खुशियां बढ़ाईं। गरम शॉल स्वेटर की सेवा में विशेष रूप से सहयोग करने वाली दिनेश गोयल जी की पुत्री व पुत्रवधू का हार्दिक धन्यवाद जो Usa में रहकर भी अपने देश के जरूरतमंदों के बारे में ध्यान रखती हैं। उनका मानना है नर सेवा ही नारायण सेवा है भूखे को भोजन खिलाना नंगे को वस्त्र देना अनपढ़ को विद्या दान देना सबसे बड़ा परोपकार है। हम सभी इसी तरह की सोच बनाएं जरूरतमंद परिवारों की मदद करें। शिक्षित समाज बनाने का प्रयास करें। यह ट्रस्ट प्रतिदिन झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को पढ़ने का सेवा देता है और उनकी जरूरत को पूरा करने का प्रयास करता है। अधिक से अधिक खुशियों का खजाना ट्रस्ट से जुड़कर इस पुण्य कार्य में भागीदार बने।

संगत ने श्री अकाल तख्त साहिब के रुतबे को फिर से दुनिया में स्थापित किया: परमजीत सिंह सरना



स्वतंत्र सिंह भुल्लर नई दिल्ली

नई दिल्ली। मैं 1962 से श्री अकाल तख्त साहिब पर होने वाले पंथिक इकट्ठों को देखता आ रहा हूँ। कल के इकट्ठा ने सिख कौम के अंदर श्री अकाल तख्त साहिब के रुतबे को फिर से दुनिया के सामने उजागर किया है। जिस तरह संगत बड़ी संख्या में पहुंची और जन्मे में रही, यह अपने आप में एक मिसाल है। इसके साथ ही यह बात भी स्पष्ट हो गई है कि सिख दौल और पंजाब के लोग श्री अकाली दल को अपनी प्रतिनिधि पार्टी

मानते हैं, और इसी कारण कल के इकट्ठा में शामिल हुए। क्योंकि पंजाब के लोग चाहते हैं कि पार्टी फिर से मजबूत होकर सामने आए। इस मौके पर श्री सुखबीर सिंह बादल ने, जो लात में फैक्चर होने के बावजूद श्रद्धा और विनम्रता के साथ इस अवसर पर पहुंचे, अपनी अंदर की भावना को जाहिर किया है। इस मौके पर सिंह साहिबान ने कौम के अंदर पैदा हुई दुविधा और खलाल को भरने के लिए और अतीत में हुई गलतियों और भूलों के लिए धार्मिक सजा देकर, आगे की

पंथिक राजनीति का रास्ता भी खोला है। इसके साथ ही हर आम सिख का चरोसा श्री अकाल तख्त साहिब में बढ़ा है। श्री अकाल तख्त साहिब से हुए सभी फैसलों को आगे श्री अकाली दल सिर झुका कर मानेगा। क्योंकि श्री अकाली दल हमेशा इस सच्चे तख्त के प्रति समर्पित रहा है और रहेगा। और पंथ की भावनाओं के अनुसार संगत की सेवा करेगा। इन शब्दों का प्रकटावा श्री अकाली दल की दिल्ली इकाई के प्रधान परमजीत सिंह सरना ने प्रेस को जारी एक बयान के माध्यम से किया।

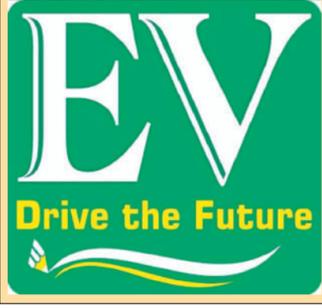
तेरी अदा इतनी कातिल नहीं!

तेरी अदा इतनी कातिल भी न थी, कि हम तुझ पर फिदा हुआ जाए। नहीं वो बात की शैदा हुआ जाए, मैं बेवफा नहीं हूँ कि परिवार की, रस्मों-रिवाजों से जुदा हुआ जाए। मैंने माना कुछ बात तो है तुझमें, वरना कहां किसी पर जाता है ध्यान! हाँ, नहीं होते हैं सभी के पूरे अरमान। खाने की टेबल पे कैसे सुनात है कान, देखा हमने सहेली पर तू थी मेहरबान! तेरी बातों में है खूब अकड़ आलिशान। ये जिंदगी की शामें बहुत कठिन है, इस आकर्षण को ऐसे ना रवाँ करना! तू तनहा है किसी से भी प्यार करना। यूँ भी खुद से पहले वो इकरार करना, नजरें झुकाना किसी पे ऐतबार करना! क्योंकि प्यार ऐसे ही नहीं हो जाता है। यूँ तेरी अदाएं अभी-भी कातिल नहीं, कि तुझ पर कोई भी फिदा हो जाए। ये सच है तू खुद में पैदा कर वो बात, कि तुझ पर कभी कोई शैदा हो जाए।

संजय एम. तराणेकर

- सौजन्य -

ईवी ड्राइव द फ्यूचर



इन-हाउस आरएंडडी में उत्कृष्टता के लिए मिला लोहम को डीएसआईआर प्रमाणन पत्र

परिवहन विशेष न्यूज

अपने टिकाऊ खनिज उत्पादन और बैटरी जीवनचक्र प्रबंधन को आगे बढ़ाने के लिए लोहम को प्रतिबद्धता को डीएसआईआर प्रमाणन की मान्यता मिली है, जिससे अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं में वृद्धि होगी और भारत के नवाचार-संचालित ऊर्जा परिवर्तन में योगदान मिलेगा।

एकीकृत बैटरी रीपैरिंग, मटेरियल रिसाइक्लिंग और रिफाइनिंग के माध्यम से टिकाऊ महत्वपूर्ण खनिजों के अग्रणी उत्पादक और प्रोसेसर लोहम को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) प्रमाणन प्राप्त हुआ है। यह मान्यता उसे टिकाऊ महत्वपूर्ण खनिज उत्पादन और एकीकृत बैटरी जीवनचक्र प्रबंधन के लिए अनुसंधान और

विकास को आगे बढ़ाने में कंपनी के प्रयासों को दी गई है।

लोहम अपने वार्षिक राजस्व का 5% और अपने कुल कार्यबल का 10% अनुसंधान एवं विकास के लिए आवंटित करता है। कंपनी एक समर्पित 40,000 वर्ग फुट का इनोवेशन सेंटर संचालित करती है, जिसमें 100 से अधिक अनुसंधान एवं विकास वैज्ञानिकों की एक टीम है जो महत्वपूर्ण खनिजों की एक परिपत्र अर्थव्यवस्था के लिए बाजार-तैयार समाधान विकसित करने पर केंद्रित है।

23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 51/96-सीमा शुल्क और उसके बाद के संशोधनों के तहत दिया गया डीएसआईआर प्रमाणन इस बात की पुष्टि करता है कि लोहम की आंतरिक अनुसंधान एवं विकास

गतिविधियाँ नवाचार और वैज्ञानिक कठोरता के आवश्यक मानकों को पूरा करती हैं। प्रमाणन कंपनी को अपने अनुसंधान के लिए अतिरिक्त संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है, जिसमें अनुसंधान एवं विकास व्यय के लिए कर और सीमा शुल्क पर छूट शामिल है।

लोहम में अनुसंधान एवं विकास तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रमुख डॉ. चिंदबरम मंडन ने कहा, रहम डीएसआईआर से यह मान्यता प्राप्त करके प्रसन्न हैं। यह प्रमाणन हमारी अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हमारे चल रहे प्रयासों का समर्थन करेगा तथा वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में योगदान देगा। यह प्रमाणन एक नवाचार केंद्र के रूप में भारत के विकास में योगदानकर्ता के रूप में लोहम की भूमिका की पुष्टि करता है।



जिप इलेक्ट्रिक ने 20 मिलियन से अधिक डिलीवरी पूरी की, वित्त वर्ष 26 के अंत तक 1,00,000 ई-बाइक बेड़े का लक्ष्य

परिवहन विशेष न्यूज

कंपनी ने हाल ही में जेप्टो, ब्लिंकिट, बिगबास्केट नाउ जैसे त्वरित-वाणिज्य प्लेटफॉर्मों के लिए 20.5 मिलियन डिलीवरी पूरी की है, और इसका लक्ष्य वित्त वर्ष 30 तक अपने बेड़े का आकार वर्तमान 20,000 ईवी से बढ़ाकर 500,000 ई-बाइक करना है।

नई दिल्ली स्थित इलेक्ट्रिक वाहन लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता जिप इलेक्ट्रिक ने जेप्टो ब्लिंकिट और बिग बास्केट नाउ जैसे भागीदारों के लिए 20 मिलियन से अधिक डिलीवरी पूरी करने की उपलब्धि हासिल की, जो भारत में अपनी क्विक-कॉमर्स सेवाओं के साथ हलचल मचा रहे हैं। कंपनी का कहना है कि इन 20.5 मिलियन डिलीवरी का एक बड़ा हिस्सा पिछले 15-24 महीनों में हुआ है, जब Zepto जैसे नए जमाने के स्टार्टअप के उभरने के बाद परिदृश्य बदलना शुरू हुआ।

इस प्रक्रिया में जिप इलेक्ट्रिक का दावा है कि इसने इन क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को अपने दोपहिया वाहनों के सभी इलेक्ट्रिक बेड़े के कारण 2.5 मिलियन किलोग्राम से अधिक कार्बन उत्सर्जन को बचाने में सक्षम बनाया है, जिसमें 60% फिक्स्ड-बैटरी स्कूटर शामिल हैं, और शेष बैटरी-स्वैप विकल्प के साथ जो इसके सवार भागीदारों को अतिरिक्त मील जाने में सक्षम बनाता है। कंपनी यह भी दावा करती है कि वह देश में क्विक-कॉमर्स खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ी डीवी फ्लीट प्रदाता है, जिसके पास अकेले दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सभी क्विक-कॉमर्स डिलीवरी का 15-20% बाजार हिस्सा है।

जिप इलेक्ट्रिक, जो वर्तमान में तीन प्रमुख



बाजारों - दिल्ली-एनसीआर, बंगलुरु और मुंबई में अपनी ईवी बेड़े की सेवाएं प्रदान करती है, अब पुणे, हैदराबाद और चेन्नई सहित अधिक शहरों में विस्तार करने की योजना बना रही है, साथ ही अहमदाबाद, लखनऊ और जयपुर जैसे कुछ टियर-2 बाजारों में भी विस्तार करना चाहती है।

जिप इलेक्ट्रिक के सह-संस्थापक और सीईओ आकाश गुप्ता के अनुसार, रथे वे बाजार हैं जो अगले 12-18 महीनों में हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, और इसके साथ ही, हम इस अवधि में अपने बेड़े को मौजूदा 20,000 बाइक से बढ़ाकर 100,000 ई-बाइक तक बढ़ाएंगे। यह वह मांग है जिसे हम स्पष्ट रूप

से पूरा कर सकते हैं।"

गुप्ता ने कहा, "इन सभी कंपनियों को इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ-साथ अच्छी तरह से प्रशिक्षित राइडर पार्टनर्स की गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति की आवश्यकता है, और यहीं पर जिप आता है। चूंकि इनमें से प्रत्येक स्टार्टअप का ईएसजी और स्थिरता पर एक मजबूत फोकस है, इसलिए जिप लास्ट-माइल लॉजिस्टिक्स के इस सेगमेंट में अपने सबसे बड़े ईवी बेड़े के साथ इन खिलाड़ियों के लिए वास्तविक विकल्प बन जाता है।"

कंपनी का कहना है कि वह अपने बेड़े को बढ़ाने के लिए लेक्ट्रिक्स और ओडिसी जैसी भारतीय मूल की ईवी ओईएम के साथ काम कर

रही है। गुप्ता ने बताया, रहमने ओडिसी के साथ 40,000 यूनिट ई-बाइक और लेक्ट्रिक्स के साथ 30,000 बाइक का ऑर्डर दिया है। हमारा विचार गहराई से जाना और सही उत्पाद बनाना है जो हमारे उपयोग के मामले में फिट हो। हमने इन ओईएम के साथ मिलकर मेड-इन-इंडिया जिप ग्रीन बाइक देश भर के कई शहरों में महत्वपूर्ण विस्तार के आधार पर अगले पांच वर्षों में अपने बेड़े के आकार को 500,000 ई-बाइक तक बढ़ाना है।

ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक्स ने ई-ऑटो के लिए आकर्षक वित्तपोषण योजना के लिए इंडसइंड बैंक के साथ मिलाया हाथ

परिवहन विशेष न्यूज

इलेक्ट्रिक वाहनों में भारत की अग्रणी निर्माता ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक्स ने अपने इलेक्ट्रिक ऑटो में एल5 की रेंज के लिए आसान और किफायती वित्तपोषण प्रदान करने के लिए इंडसइंड बैंक के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के माध्यम से ठुकराल इलेक्ट्रिक का लक्ष्य भारत भर में ठुकराल इलेक्ट्रिक के डीलरशिप पर इंडसइंड बैंक के माध्यम से सक्षम ऋण तक पहुंच प्रदान करके देश के दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में पहुंचना है।

इस अवसर पर ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक्स के संस्थापक और प्रबंध निदेशक जितेंद्र ठुकराल ने कहा, "कंपनी का विजन आम जनता को ग्रीन मोबिलिटी प्रदान करना है। अपने विजन के अनुरूप हम अपने ग्राहकों को किफायती और आसान वित्तपोषण विकल्प लाने के लिए इंडसइंड बैंक को अपने धरोसेमंद भागीदार के रूप में शामिल करके प्रसन्न हैं। इंडसइंड बैंक हमारे इलेक्ट्रिक एल5 वाहन

पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक मजबूत परिसंपत्ति होगी, जो ग्राहकों को उनकी इच्छानुसार बैंकिंग और भुगतान प्रदान करेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि यह साझेदारी हमारे ग्राहकों को ग्रीन मोबिलिटी प्रदान करेगी।

इंडसइंड बैंक के कंज्यूमर फाइनेंस के प्रमुख प्रवक्ता ने कहा, रहम ठुकराल इलेक्ट्रिक के साथ उनकी इलेक्ट्रिक ऑटो की एल5 सेगमेंट में सहयोग करने के लिए उत्साहित है। पिछले कुछ वर्षों में हमने ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए अलग-अलग वित्तपोषण समाधान पेश किए हैं। हमें विश्वास है कि ठुकराल इलेक्ट्रिक के एल5 उत्पादों के वित्तपोषण के लिए पेश की गई योजना उद्योग में सर्वश्रेष्ठ होगी। यह सहयोग इंडसइंड बैंक के ग्रीन मोबिलिटी के दृष्टिकोण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारी व्यापक भौगोलिक पहुंच देश भर में ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक्स के ग्राहकों की सेवा करने में मदद करेगी।"

ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक्स ने ई-ऑटो के लिए आकर्षक वित्तपोषण योजना के लिए इंडसइंड बैंक के साथ मिलाया हाथ



लेक्ट्रिक्स ईवी अगले वित्त वर्ष 2026 में ई-मोटरसाइकिल बाजार में प्रवेश करने की बना रही है योजना

परिवहन विशेष न्यूज

लेक्ट्रिक्स ईवी ई-स्कूटर पोर्टफोलियो में एलएक्सएस सीरीज, एलएक्सएस 25 के साथ-साथ हाल ही में लॉन्च किया गया एनड्यूरो भी शामिल है। कंपनी ने पिछले चार सालों में 10,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर और 30,000 इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर बेचे हैं और अगले 12 महीनों में 25,000 से ज्यादा एनड्यूरो बेचने का लक्ष्य रखा है, संस्थापक राकेश मल्होत्रा ने एनड्यूरो के लॉन्च के मौके पर ये बात कही।

एसएआर ग्रुप की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शाखा, लेक्ट्रिक्स ईवी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बाजार में प्रवेश करके अपने मौजूदा पोर्टफोलियो का विस्तार करने की योजना बना रही है। कंपनी ने पहले ही इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के विकास और विनिर्माण में 300 करोड़ रुपये का निवेश किया है, अब उसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2026 तक 100 मिलियन अमरीकी डॉलर या 840 करोड़ रुपये (इससे अधिक) जुटाने का है।

लेक्ट्रिक्स ईवी ई-स्कूटर पोर्टफोलियो में एलएक्सएस सीरीज, एलएक्सएस 25 के साथ-साथ हाल ही में लॉन्च किया गया एनड्यूरो शामिल है। संस्थापक राकेश मल्होत्रा ने



बताया कि कंपनी अगले 12 महीनों में 25,000 से अधिक एनड्यूरो बेचने का लक्ष्य रखा है, साथ ही उन्होंने बताया कि उत्पाद 2 फरवरी, 2025 से अपने ग्राहकों तक पहुंचाया जाएगा।

कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल विकसित करना शुरू कर दिया है और इसे वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही में भारतीय बाजार में लाने की योजना बना रही है। उन्होंने आगे कहा, रहम इसे (ई-मोटरसाइकिल) इस तरह से करना चाहते हैं कि यह एक वैश्विक मंच बन जाए। ई-मोटरसाइकिल के लिए, लेक्ट्रिक्स ईवी अच्चे निर्यात का लक्ष्य बना रहा है क्योंकि वे विदेशी देशों को अपने वाहनों के संभावित खरीदारों के रूप में देखते हैं।

डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स ने ईवी चार्जर्स के लिए थंडरप्लस के साथ साझेदारी की

परिवहन विशेष न्यूज

डेल्टा के स्थानीय स्तर पर निर्मित 4 किलोवाट रेंक्टफायर मॉड्यूल थंडरप्लस के फास्ट चार्जर्स को शक्ति प्रदान करेंगे, जो भारत के कम वोल्टेज वाले दोपहिया और तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों में कुशल और टिकाऊ चार्जिंग समाधानों की बढ़ती मांग को पूरा करेगा।

डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग समाधान प्रदान करने वाली कंपनी थंडरप्लस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के हिस्से के रूप में, डेल्टा 2 व्हीलर और 3 व्हीलर सेगमेंट में कम वोल्टेज वाले ईवी के लिए थंडरप्लस के फास्ट चार्जर्स का समर्थन करने के लिए, तमिलनाडु के कृष्णागिरी में अपनी सुविधा में निर्मित उच्च दक्षता वाले 4kW रेंक्टफायर मॉड्यूल की आपूर्ति करेगा।

93% तक की ऊर्जा दक्षता वाले ये रेंक्टफायर विश्वसनीय और टिकाऊ बिजली समाधान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के प्रबंध निदेशक, निरंजन नायक ने इस बात पर जोर दिया कि यह सहयोग भारत के ईवी संक्रमण का समर्थन करने के लिए ऊर्जा-कुशल समाधान प्रदान करने के कंपनी के उद्देश्य के अनुरूप है। उन्होंने इस उपलब्धि को हासिल करने में बंगलुरु और इसके कृष्णागिरी विनिर्माण स्थल में डेल्टा की अनुसंधान और विकास क्षमताओं की भूमिका पर प्रकाश डाला।

डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बिजनेस हेड मंजुला गिरीश ने कहा कि रेंक्टफायर्स को थंडरप्लस के फास्ट चार्जर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि यह साझेदारी भारत के बढ़ते ईवी बाजार को संभावित करने के



लिए स्थानीय विनिर्माण के साथ उन्नत प्रौद्योगिकी के एकीकरण को उजागर करती है।

थंडरप्लस के सीईओ राजीव वाईएसआर ने कहा कि यह सहयोग बिजली समाधानों में डेल्टा

की विशेषज्ञता को थंडरप्लस के कुशल ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के फोकस के साथ जोड़ता है। उन्होंने बताया कि चार्ज, जो अनुकूलन योग्य है, मूल उपकरण निर्माताओं

(ओईएम) और अंतिम उपयोगकर्ताओं की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

इस साझेदारी का उद्देश्य चार्जिंग डाउनटाइम

को कम करके और एक स्थायी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का समर्थन करके भारत के 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ईवी उपयोगकर्ताओं के लिए चार्जिंग अनुभव को बेहतर बनाना है। डेल्टा के रेंक्टफायर मॉड्यूल के साथ डिज़ाइन किए गए चार्जर्स का उद्देश्य वैश्विक मानकों को भारतीय बाजार की जरूरतों के साथ संतुलित करना है। थंडरप्लस पहले से ही 2 व्हीलर और 3 व्हीलर सेगमेंट में ओईएम के साथ जुड़ चुका है और इस सहयोग को और मजबूत करने के लिए सह-ब्रैंडिंग के अवसरों का उपयोग करने की योजना बना रहा है।

2 व्हीलर और 3 व्हीलर वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता के कारण भारत का ईवी बाजार तेजी से बढ़ रहा है। इस सहयोग के तहत उत्पादित रेंक्टफायर और चार्जर्स से देश में एक मजबूत ईवी इकोसिस्टम के विकास में योगदान मिलने की उम्मीद है।

एडवेंचर स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर में नौकरी के अवसर और करियर विकल्प



विजय गर्ग



एडवेंचर स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एडवेंचर स्पोर्ट्स में प्रशिक्षण प्रदान करने में विशेषज्ञ है, चाहे वह वॉटर स्पोर्ट्स जैसे स्क्वा डाइविंग, व्हाइट वॉटर राफ्टिंग, कयाकिंग, कैनोइंग, क्लिफ डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, यॉट रेसिंग, पावरबोट रेसिंग, विंड सर्फिंग आदि हो। हवाई खेल जैसे बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग, स्काई सर्फिंग आदि, या भूमि साहसिक खेल जैसे रॉक क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग, माउंटेन बाइकिंग, स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, ट्रेकिंग, एडवेंचर रेसिंग, भूमि और बर्फ नौकायन आदि। साहसिक पर्यटन, पहाड़ी रिसॉर्ट संस्कृति के बारे में जनता के बीच जागरूकता फैलाने और नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी, एक्सप्रेस आदि जैसे मीडिया चैनलों की भागीदारी के साथ, लोग अपने आसपास साहसिक खेल गतिविधियों के बारे में अधिक जागरूक हो गए हैं और एक साहसिक छुट्टी की योजना बनाना चाहते हैं। पेशेवर प्रशिक्षक के रूप में इन विशेषज्ञों की मांग पिछले कुछ वर्षों में कई गुना बढ़ गई है। इस प्रकार एडवेंचर टूरिज्म के इस क्षेत्र में एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रशिक्षकों का अच्छा भविष्य है। साहसिक खेलों में जनसंचार माध्यमों की भागीदारी के विश्वव्यापी दृष्टिकोण के कारण उच्च स्तर पर इस क्षेत्र से बहुत सारा ग्लैमर भी जुड़ गया है। एक सफल साहसिक खेल प्रशिक्षक बनने के लिए एक सफल प्रशिक्षक के पास क्षेत्र में आवश्यक जानकारी और विशेषज्ञता होनी चाहिए। आवश्यक विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति निम्नलिखित अल्पकालिक और पूर्णकालिक दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों में से एक या अधिक को अपना करियर बना सकता है। इसमें बहुत अधिक मेहनत और प्रयास की आवश्यकता होती है लेकिन साथ ही यह किसी के करियर के निर्माण के लिए बहुत अधिक संभावनाएं प्रदान करता है। पूर्व खिलाड़ियों के साथ-साथ कड़ी मेहनत की इच्छा और क्षमता

वाले युवा ऊर्जावान लोग, अब साहसिक खेलों से जुड़े नाम और प्रसिद्धि के साथ-साथ पैसा और संतुष्टि दोनों प्राप्त कर सकते हैं। साहसिक खेल प्रशिक्षक पात्रता शैक्षणिक योग्यता एडवेंचर स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आवश्यक वांछनीय योग्यता एक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 12 वीं कक्षा है (हालांकि यह अनिवार्य नहीं है) इसके बाद किसी भी एडवेंचर स्पोर्ट्स संस्थान से प्रमाणन प्राप्त करना होगा। ऑनलाइन शिक्षण संसाधन महत्वपूर्ण: जल-आधारित खेलों के लिए तैराकी का अच्छा कौशल अनिवार्य है। इसके अलावा, विदेशी साहसिक खेल प्रेमियों को संभालने के लिए अंग्रेजी या कुछ विदेशी भाषाओं में बनने के लिए एक अच्छे के पास क्षेत्र में आवश्यक जानकारी और विशेषज्ञता होनी चाहिए। आवश्यक विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति निम्नलिखित अल्पकालिक और पूर्णकालिक दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों में से एक या अधिक को अपना करियर बना सकता है। इसमें बहुत अधिक मेहनत और प्रयास की आवश्यकता होती है लेकिन साथ ही यह किसी के करियर के निर्माण के लिए बहुत अधिक संभावनाएं प्रदान करता है। पूर्व खिलाड़ियों के साथ-साथ कड़ी मेहनत की इच्छा और क्षमता

के लिए किसी औपचारिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है जो स्वयं खिलाड़ी के रूप में साहसिक खेलों से जुड़े रहे हैं। पूर्व साहसिक खेल खिलाड़ियों को एक खिलाड़ी के रूप में खेल के अपने ज्ञान और अनुभव के कारण सहायक खेल प्रशिक्षक (आवश्यक प्रमाणीकरण या लाइसेंस प्राप्त करने के बाद) के रूप में नौकरी मिल सकती है। सहायक के रूप में क्षेत्र में कुछ अनुभव के साथ, वे समय के साथ मुख्य प्रशिक्षक या मुख्य प्रशिक्षक के रूप में ऊपरी पद पर आसानी हो सकते हैं। हालांकि, वे अभ्यर्थी जिनके पास गैर-खेल पृष्ठभूमि है, लेकिन वे ऊर्जावान हैं और खेल का अच्छा ज्ञान रखते हैं, वे औपचारिक प्रशिक्षण ले सकते हैं और नीचे दिए गए निर्देशों का पालन खेल प्रशिक्षकों के लिए आवश्यक कौशल साहसिक खेल प्रशिक्षकों में खेल के प्रति उत्साह, उत्कृष्ट संचार कौशल, आत्मविश्वास जगाने और प्रतिभागियों को प्रेरित करने की क्षमता होनी चाहिए। उनमें दृढ़ संकल्प और धैर्य, अच्छा संगठनात्मक कौशल, संवेदनशील और सहायक दृष्टिकोण होना चाहिए। उनमें शारीरिक सहनशक्ति और खेल में सभी की भागीदारी के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। एडवेंचर स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर कैसे बनें? उन उम्मीदवारों

के लिए किसी औपचारिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है जो स्वयं खिलाड़ी के रूप में साहसिक खेलों से जुड़े रहे हैं। पूर्व साहसिक खेल खिलाड़ियों को एक खिलाड़ी के रूप में खेल के अपने ज्ञान और अनुभव के कारण सहायक खेल प्रशिक्षक (आवश्यक प्रमाणीकरण या लाइसेंस प्राप्त करने के बाद) के रूप में नौकरी मिल सकती है। सहायक के रूप में क्षेत्र में कुछ अनुभव के साथ, वे समय के साथ मुख्य प्रशिक्षक या मुख्य प्रशिक्षक के रूप में ऊपरी पद पर आसानी हो सकते हैं। हालांकि, वे अभ्यर्थी जिनके पास गैर-खेल पृष्ठभूमि है, लेकिन वे ऊर्जावान हैं और खेल का अच्छा ज्ञान रखते हैं, वे औपचारिक प्रशिक्षण ले सकते हैं और नीचे दिए गए निर्देशों का पालन खेल प्रशिक्षकों के लिए आवश्यक कौशल साहसिक खेल प्रशिक्षकों में खेल के प्रति उत्साह, उत्कृष्ट संचार कौशल, आत्मविश्वास जगाने और प्रतिभागियों को प्रेरित करने की क्षमता होनी चाहिए। उनमें दृढ़ संकल्प और धैर्य, अच्छा संगठनात्मक कौशल, संवेदनशील और सहायक दृष्टिकोण होना चाहिए। उनमें शारीरिक सहनशक्ति और खेल में सभी की भागीदारी के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। एडवेंचर स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर कैसे बनें? उन उम्मीदवारों

पात्र बनाता है। साहसिक खेल प्रशिक्षक के लिए नौकरी विवरण साहसिक खेलों के लिए न केवल खेल कौशल की आवश्यकता होती है, बल्कि साहसिक कार्य करने के लिए बहुत अधिक प्रेरणा भी आवश्यकता होती है क्योंकि इनमें एक निश्चित मात्रा में जोखिम लेना भी शामिल होता है। इस प्रकार एक साहसिक खेल प्रशिक्षक की नौकरी का उचित स्पॉर्टिंग कौशल सिखाने से कहीं अधिक है। उनके काम में समूह पहले के माध्यम से समूहों का मार्गदर्शन करना, उचित स्पॉर्टिंग तकनीक सिखाना, रिसर्चों, कैंपिनिंग, हार्नेस और अन्य जीवन सहायक उपकरणों की उचित देखभाल और रखरखाव सिखाना शामिल है क्योंकि वे किसी भी प्रकार के कार्य को ठीक से करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, वह शिविरार्थियों और कर्मचारियों को नए खेल आज़माने, शिविर जीवन के अन्य पहलुओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक साहसिक खेल प्रशिक्षक को वे सभी कर्तव्य निभाने होते हैं जो साहसिक/खेल निदेशक, ग्राम निदेशक, कार्यक्रम समन्वयक या शिविर निदेशक द्वारा उसे सौंपे जा सकते हैं। सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम होने के लिए प्रमाणन या लाइसेंस प्रदान किया जाता है जो उन्हें साहसिक खेल प्रशिक्षक बनने के लिए

सीखना जारी रहना चाहिए

विजय गर्ग

सीखना संभावनाओं के दरवाजे खोलता है, अगर इसे रोक दिया जाता है तो हम उस दरवाजे को बंद कर रहे हैं और अपने विकास में बाधा डाल रहे हैं सीखना एक आवश्यक और आजीवन प्रक्रिया है। यह मानव विकास और विकास की आधारशिला है। हालांकि, ज्ञान प्राप्त करने की यात्रिकी से परे सीखने की सूक्ष्म कला निहित है - एक दृष्टिकोण जो जिज्ञासा, रचनात्मकता, अनुकूलनशीलता और खोज के जुनून पर जोर देता है। जिज्ञासा - यह शब्द अपने आप में कहता है कि यह आजीवन सीखने का ईंधन है। इसके मूल में, सीखने की कला में तथ्यों और कौशलों के संघर्ष से कहीं अधिक शामिल है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है जो बौद्धिक, भावनात्मक और अनुभवमय आयामों को एकीकृत करती है। सीखना तब कलात्मक हो जाता है जब वह उद्देश्यपूर्ण, आनंदमय और किसी व्यक्ति के मूल्यों और आकांक्षाओं से गहराई से जुड़ा हो। एक कठोर, मानकीकृत दृष्टिकोण के विपरीत, सीखने की कला यह मानती है कि हर किसी के पास अद्वितीय ताकत, रुचियां और दुनिया को समझने के तरीके हैं। यह शिक्षार्थियों को अपने व्यक्तित्व को अपनाने, विविध दृष्टिकोणों का पता लगाने और सीखने की प्रक्रिया में अर्थ खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है क्योंकि ज्ञान केवल औपचारिक शिक्षा या कितना पढ़ने से नहीं आता है बल्कि यह जीवन, बातचीत, अनुभवों और अप्रत्याशित मुठभेड़ों से आता है। व्यक्तियों को नए दृष्टिकोणों के प्रति खुला रहना चाहिए, चाहे वे विभिन्न संस्कृतियों, व्यवसायों या आयु समूहों से हों। कैरल ड्रवैक द्वारा लोकप्रिय विकास मानसिकता, यह विश्वास है कि बुद्धिमान और क्षमताओं को सम्पूर्ण और कड़ी मेहनत के माध्यम से विकसित किया जा सकता है जो एक निश्चित मानसिकता के विपरीत है जो मानती है कि क्षमताएं स्थिर हैं। विकास की मानसिकता के साथ, असफलताओं को अक्सर विफलताओं के बजाय सीखने के अवसरों के रूप में देखा जाता है जबकि चुनौतियों को सीखने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अपनाया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना जानता है, आगे बढ़ने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। विनम्र बने रहना, और दूसरों से प्रतिक्रिया, आलोचना और रचनात्मक इनपुट के लिए खुला रहना किसी व्यक्ति को अपनी समझ को बेहतर बनाने और परिष्कृत करने में मदद कर सकता है। एक और महत्वपूर्ण कारक जो सीखने की कला को बढ़ाता है वह है जुनून की कला। जो शिक्षार्थी अपनी रुचि से मेल खाने वाले विषयों को अपनाते हैं, वे प्रवाह की स्थिति में प्रवेश करते हैं, जहां प्रयास सहज महसूस होता है, और प्रक्रिया आंतरिक रूप से फायदेमंद हो जाती है। जुनून प्रेरणा को बनाए रखता है और गहन जुड़ाव को बढ़ावा देता है, जिससे महारत हासिल होती है। अपने आप को समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ घेरना जो सीखने को प्राथमिकता देते हैं, चर्चाओं में शामिल होना, कार्यशालाओं में भाग लेना या परियोजनाओं पर सहयोग करना किसी व्यक्ति के लिए सीखने और बढ़ने की चुनौती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सबसे प्रतिभाशाली दिमाग वाले ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिन्हें अन्य लोग हल्के में ले सकते हैं। किसी को 'क्यों' और 'कैसे' पूछने की आदत डालनी चाहिए और न केवल अमूर्त विचारों के बारे में, बल्कि रोजमर्रा की स्थितियों में भी, क्योंकि ये प्रश्न किसी की सोच को सीमाओं को तोड़ते हैं और गहरी अंतर्दृष्टि तक ले जा सकते हैं। यह हमेशा तब होता है जब कोई सीखने को एक के रूप में अपनाता है। आजीवन अभ्यास, जो व्यक्ति को व्यक्तित्व और व्यावसायिक परिवर्तन के लिए संभावनाओं, विचारों और अवसरों की दुनिया के लिए खोल सकता है। सीखने को कला के रूप में समझना इसे एक साधारण कार्य से आत्म-अन्वेषण और सीखने के जुनून को विकसित करने में महारत हासिल करने की गहन यात्रा में बदल देता है जो कभी बड़ना बंद नहीं होगा। सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस 'टैक्नोलॉजी के दो पहलू: विजय गर्ग

पिछले 60-70 साल में जिस तरह विज्ञान की नियामताओं और टैक्नोलॉजी की आसानीयने ने जीवन की रूपरेखा बदली है, सोचा जाए तो लगेगा कि इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता? सब कुछ संभव ही नहीं बल्कि चुटकी बजाते ही आलादीन के चिराग की तरह 'जो हुकम मेरे आका' जैसा हो सकता है। मानव और मशीन का गठजोड़: जब दशकों पहले दिल्ली के प्रगति मैदान में लगे मेले में पहली बार टैलीविजन और उसमें से बोलते चेहरे की आवाज लोगों ने सुनी तो आंख और कान पर यकीन नहीं हो पा रहा था। हर व्यक्ति की जुबान पर चर्चा थी। टैलीफोन का आविष्कार बहुत पहले हो गया था लेकिन जब एक डिविजा के आकार में इसका वज्रद समा गया और दुनिया में कहीं भी बिना किसी तार या कनेक्शन के बात होने लगी तो सोचा कि 'ऐसा भी हो सकता है' और जब बात करने वाले एक-दूसरे को देख भी सकते हों, चाहे सात समंदर पार हों, तब यह अजूबा ही लगा। कम्प्यूटर का बड़ा-सा डिब्बा अपने पूरे ताम-झाम के साथ घरों और दफ्तरों में पहुंचा तो यह कमाल लगा। इसकी बदौलत कुछ भी करना सुगम हुआ तो वाहवाही करनी ही थी। अब यह छोटे से मोबाइल

फोन की स्क्रीन हो या आदमकद टी.वी. स्क्रीन, ज्ञान बतियाने और बांटने से लेकर खेल खेलना और मनोरंजन का लुत्फ उठाना उंगलियों से बटन दबाते ही होने लगा है। मुंह से निकलता है कि 'अब और क्या'? इसका जवाब भी मिल गया और हमारे सामने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का संसार आ गया। इसके आगे क्या होगा उसके लिए आश्चर्यचकित होने का स्थान अब जिज्ञासा और उत्सुकता ने ले लिया है। इंसान का दिमाग क्या और कहां तक सोच सकता है, उसे व्यवहार में लाकर एक तरह से किसी भी चीज को काया बलट कैसे हो सकती है या की जा सकती है, इतना ही समझ लेना काफी है। जब हम इस नई टैक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं नजर आता। वह मशीन को अपने इशारों पर नचा सकता है या कहें कि वह सब करवा सकता है जो उसके दिमाग में चल रहा है। यहाँ इस बात पर गौर करना होगा कि मशीन अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। कमान इंसान के हाथ में रहती है, ठीक उसी तरह जैसे चिराग से निकले जिन को वही करना होता है जो आका का हुकम हो। असावधानी या गलतफहमी के कारण गलती हो गई तब यह मशीन छुट्टे सांड की

तरह कितनी तबाही मचा सकते हैं सक्षम है, इसकी कल्पना भी करना कठिन है। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की गहराई तक जाने की एक सामान्य व्यक्ति को न तो जरूरत है और न ही उसके लिए आसान है। इतना ही समझना पर्याप्त है कि अब इसके इस्तेमाल से घर बैठे ही अपने बही खाते, उतार-चढ़ाव, फेरबदल, बाजार की उठा पटक पर नजर ही नहीं, उसमें अपने हिसाब से परिवर्तन किया जा सकता है। जो बिजनेस करते हैं, उद्योग धंधे चलाते हैं और जिनके लिए प्लक ड्रपकने का अर्थ लाडों-करोड़ों के बलट-न्यार है, यह टैक्नोलॉजी वरदान है। इसी तरह जो प्रोफेशनल व्यक्ति टेक्स, वकालत, कंसल्टेंसी या फिल्म निर्माण के क्षेत्र में हैं, वे महीनों का काम दिनों और घंटों का मिनिटों में कर सकते हैं। हमारे देश में योग्यता की कोई कमी नहीं है लेकिन इसी के साथ कविल बनाने वाली और कार्यकुशलता बढ़ाने वाली का जरूरत है। इसका परिणाम यह होता है कि लोग गलती करने के बाद सीखते हैं और दोड़ में पिछड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए जब मशीन में पुराने आंकड़े या डाटा डाला या फ्रीड किया जाता है तो उसमें से जो रिजल्ट निकलेगा वह तो कचरा ही होगा। दुर्भाग्य से यही कचरा



हमारे लिए नीतियां बनाने वाले इस्तेमाल में लाते हैं और नतीजे के तौर पर असफलता ही हाथ लगती है। शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, बेरोजगारी, गरीबी हटाने से लेकर प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण तथा जनसंख्या तक के आंकड़े दसियों साल पुराने होने के कारण हरेक क्षेत्र

में खिंचावनी और अपना दोष दूसरे के सिर मढ़ने जैसा वातावरण है। सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग चाहे राजनीति हो या आर्थिक विशेषज्ञ जिन पर जन कल्याण की योजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी है वे योग्य तथा प्रतिभाशाली नहीं होंगे, चाहे दुनिया कितनी आगे बढ़ जाए, हमारा पीछे

रहना भाग्य के लेखे की तरह है। लाभ और हानि की तुलना आवश्यक: आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस टैक्नोलॉजी के जितने फायदे हैं, उनकी तुलना में नुकसान भी कम नहीं हैं बशर्ते कि सावधानी न बरती गई हो। नकली आवाज, वही चेहरा, हावभाव, उठने-बैठने से लेकर बातचीत

करने का अंदाज तक हू-ब-हू कॉपी किया जा सकता है। साइबरक्राइम के खतरे शुरू हो चुके हैं, लूटपाट और चोरी-डकैती के लिए घर में संध लगाने की जरूरत नहीं, इस टैक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से यह सब कुछ आसानी से किया जा सकता है। डिजिटल अरैस्ट, बिना जानकारी खाते खाती, जिंदगी भर की बचत पल भर में साफ, कौन अपना कौन पराया और कौन बन जाए वगैरत और बेगाना, कुछ भी हो सकता है। जरूरी है यह समझना कि चाहे कोई कितना भी अपना बनकर कोई जानकारी मांगे तो उसे पहली बार तो टाल ही दें। फिर पूरी जांच-पड़ताल करें, बैंक से पूछें, दोस्तों और रिश्तेदारों से सांझा करें और तब ही कुछ करें या कहें जब आवश्यक हो जाए कि कुछ गड़बड़ नहीं है। डराने या धमकाने और गिफतार होने की संभावना पर यकीन न करें। यही मानकर चलें कि नकल का बाजार गरम है और अकल का इस्तेमाल करना है। बहकने या भुलावे की कोई गुंजाइश नहीं, जो नहीं दिख रहा उसे देखने की कोशिश करें। इतना ही करना एक आम आदमी के लिए पर्याप्त है वरना लुट्टे तो अपना जाल बिछाए बैठे ही हैं।

फल-सब्जियों को चमकाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल

विजय गर्ग

फल और सब्जियों को चमकाने के लिए अक्सर केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इन रसायनों का उद्देश्य फल-सब्जियों को अधिक आकर्षक और ताजा दिखाना होता है, लेकिन इससे उनके पोषण और सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कुछ प्रमुख केमिकल्स जो इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होते हैं: 1. वैक्स कोटिंग: फलों, जैसे सेब, संतरा और अंगूर पर पॉलिश करने के लिए वैक्स का इस्तेमाल होता है। प्राकृतिक वैक्स, जैसे कैरनोबा वैक्स, अपेक्षाकृत सुरक्षित होते हैं, लेकिन सिंथेटिक या पेट्रोलियम आधारित वैक्स स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ये वैक्स फलों की सतह पर बैक्टीरिया या फण्ड को पनपने से रोकते हैं और उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं। 2. एथीफॉन: कच्चे फलों को पकाने और रंग चमकाने

के लिए एथीफॉन या कार्बाइड जैसे रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग प्रतिबंधित है, क्योंकि यह गैस पैदा करता है, जो कैसर और अन्य गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। 3. डाई और रंग: सब्जियों जैसे गाजर और मिर्च को अधिक लाल और चमकीला दिखाने के लिए रंगों का उपयोग होता है। ये कृत्रिम रंग, खासकर जो खाने के लिए सुरक्षित नहीं हैं, गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। 4. एंटीफंगल और प्रिजर्वेटिव: फलों और सब्जियों पर कवक और फफूंदी को रोकने के लिए थायाबेडाजोल और अन्य रसायन लगाए जाते हैं। इनका अत्यधिक उपयोग विषाक्तता और एलर्जी का कारण बन सकता है स्वास्थ्य पर प्रभाव: 1. त्वचा की समस्याएं: केमिकल्स से एलर्जी या त्वचा में जलन हो सकती है। 2. अंदरूनी विषाक्तता: ये रसायन लंबे समय तक शरीर में रहकर आंतरिक अंगों

को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 3. कैंसर का खतरा: कुछ रसायन, जैसे कैल्शियम कार्बाइड, कैंसरजनक हो सकते हैं। 4. गर्भावस्था पर प्रभाव: ये हानिकारक केमिकल्स गर्भवस्थ शिशु के विकास में बाधा डाल सकते हैं। रोकथाम और सावधानियां: 1. साफ पानी से धोना: फलों और सब्जियों को अच्छी तरह धोकर इन रसायनों को हटाया जा सकता है। 2. बेकिंग सोडा या नमक का उपयोग: इन्हें पानी में मिलाकर धोने से रसायन हटाने में मदद मिलती है। 3. ऑर्गेनिक खरीदें: जैविक उत्पादों में रसायनों का उपयोग न्यूनतम होता है। 4. छिलका हटाएं: यदि संभव हो, तो फलों का छिलका उतारकर खाएं। सरकार और संबंधित एजेंसियों को इन रसायनों के उपयोग पर सख्त नियंत्रण रखना चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य उत्पाद मिल सकें। सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब



आरबीआई एमपीसी की बैठक आज से शुरू, एक्सपर्ट- रेपो रेट अपरिवर्तित रहने की संभावना

परिवहन विशेष न्यूज

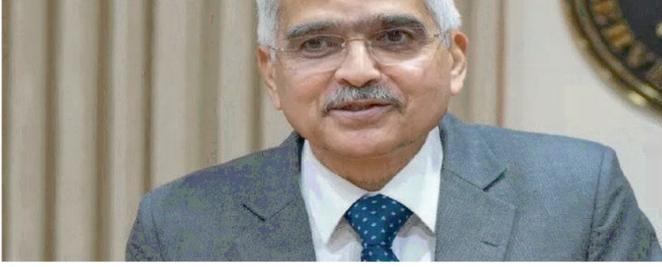
हर दो महीने में भारतीय रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक होती है। इस बैठक में बढ़ती महंगाई और देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए रेपो रेट (Repo Rate) में बदलाव या स्थिरता को लेकर फैसला लिया जाता है। आज से आरबीआई एमपीसी बैठक शुरू हो गई। एक्सपर्ट के अनुसार इस एमपीसी बैठक में भी रेपो रेट को स्थिर रखा जा सकता है।

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज से शुरू हो गई है। इस बैठक के फैसलों का एलान 6 दिसंबर 2024 (शुक्रवार) को किया जाएगा। पिछले एक साल से ज्यादा समय से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस बैठक में भी रेपो रेट स्थिर रहने का अनुमान जताया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए यथास्थिति बनाए रखेगा।

एमपीसी की घोषणा पर अर्थव्यवस्था में इसके संभावित प्रभावों के लिए बारीकी से नजर रखी जाएगी। आइए जानते हैं कि रिजर्व एस्टेट से जुड़े दिग्गजों की क्या प्रतिक्रिया है।

क्या कहते एक्सपर्ट
हम दिसंबर तिमाही में ब्याज दरों में कमी की संभावना पर ध्यान दे रहे हैं। यह रिजर्व एस्टेट सेक्टर के लिए एक लंबी प्रतीक्षित खबर होगी। सिर्फ लजरी हाउसिंग ही नहीं बल्कि पूरे सेक्टर को प्रोत्साहित करेगी। होम बायर्स को तो लाभ मिलेगा ही, निवेशकों

RBI MPC 2024



का उत्साह भी बढ़ेगा।

कांटेटी गुप के डायरेक्टर, अभित मोदी
एक्सपर्ट गुप के डायरेक्टर, संजय शर्मा के मुताबिक यह फैसला केवल रिजर्व एस्टेट क्षेत्र के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के घर खरीदारों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब रेपो दर घटती है, तो होम लोन की ब्याज दरें भी कम हो जाती हैं, जिससे घर खरीदने की प्रक्रिया सस्ती और अधिक सुलभ हो जाती है।

रहेजा डेवलपर्स के वाईस प्रेजिडेंट, मोहित कालिया के अनुसार रेपो रेट में कटौती रिजर्व एस्टेट सेक्टर के लिए एक बड़ा सकारात्मक कदम साबित होगी। इससे होम बायर्स को कर्ज की बढ़ती ब्याज दरों से राहत मिलेगी और वे निवेश के लिए प्रोत्साहित होंगे। पिछले दो सालों में रिजर्व एस्टेट सेक्टर में जो तेजी आई है, उसका एक बड़ा कारण आरबीआई की नीतियां रही हैं। खासकर रेपो रेट में एक साल से ज्यादा

समय से कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे बाजार में स्थिरता बनी रही। अब हम उम्मीद करते हैं कि इस बार आरबीआई रेपो रेट में कुछ कटौती कर सकता है। अगर आरबीआई दरों में कटौती करता है, तो इससे होम लोन की ब्याज दरें भी कम होंगी, और होम बायर्स के लिए ईएमआई पर दबाव नहीं पड़ेगा। इससे रिजर्व एस्टेट सेक्टर में और भी तेजी आएगी।

सौरभ सहारन, गुप मैनेजिंग डायरेक्टर एचसीबीएस डेवलपमेंट

नंदनी गर्ग, निदेशक, राजदरबार वेंचर्स ने कहा कि रेपो दर के फैसले रिजर्व एस्टेट क्षेत्र के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आरबीआई द्वारा रेपो दर में कटौती से उधार लेने की लागत कम हो जाएगी। ऐसे में बाजार में नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा। रिजर्व एस्टेट उद्योग रेपो दर की घोषणाओं पर

गहरी नजर रखता है, क्योंकि आरबीआई द्वारा किए गए बदलाव बाजार की स्थितियों को काफी प्रभावित कर सकते हैं। दर में कटौती से उधार लेने की लागत कम हो सकती है, इससे घर खरीदने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा और निवेश आकर्षित होगा, जिससे अंततः बढ़ावा मिलेगा।

नीरज शर्मा, एमडी, एस्कॉन इंफ्रा रियल्टर
कुशाग्र अंसल, डायरेक्टर अंसल हाउसिंग के अनुसार रिजर्व एस्टेट क्षेत्र एक महत्वपूर्ण बिंदु पर खड़ा है जहां संभावित रेपो दर में कटौती एक गेम-चेंजर हो सकती है। यह न केवल घर खरीदारों के लिए वित्तीय भार को हल्का करेगा बल्कि बाजार में नई गति लाएगा, मांग को बढ़ावा देगा और दीर्घकालिक निवेश को आकर्षित करेगा। यह कदम सतत विकास को बढ़ावा दे सकता है, जिससे व्यापक अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।

तेल कंपनियों ने अपडेट किया पेट्रोल-डीजल के दाम, फटाफट चेक करें लेटेस्ट रेट

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम जारी कर दिया है। रोजाना सुबह 6 बजे फ्यूल प्राइस अपडेट होते हैं। इनकी कीमत वैश्विक बाजार में कूट ऑयल की कीमतों के आधार पर तय होती है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। आइए जानते हैं कि देश के महानगरों समेत बाकी शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम कितने हैं।



इनके दाम जस के तस बने हुए हैं। आइए इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए जानते हैं कि महानगर और बाकी शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol- Diesel Price 4 December 2024) क्या है?

महानगरों में पेट्रोल-डीजल के दाम

दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये और डीजल की कीमत 87.62 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.44 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89.97 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104.95 रुपये प्रति लीटर और

डीजल 91.76 रुपये प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 92.34 रुपये प्रति लीटर है।

बाकी बड़े शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम

नोएडा: पेट्रोल 94.83 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.96 रुपये प्रति लीटर
गुरुग्राम: पेट्रोल 95.19 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.05 रुपये प्रति लीटर

बंगलुरु: पेट्रोल 102.86 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.94 रुपये प्रति लीटर

चंडीगढ़: पेट्रोल 94.24 रुपये प्रति लीटर और डीजल 82.40 रुपये प्रति लीटर

हैदराबाद: पेट्रोल 107.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.65 रुपये प्रति लीटर

जयपुर: पेट्रोल 104.88 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.36 रुपये प्रति लीटर

पटना: पेट्रोल 105.18 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.04 रुपये प्रति लीटर

आज फोकस में Niva Bupa, HDFC Bank समेत कई शेयर, निवेशक धड़ाधड़ कर रहे खरीदारी

परिवहन विशेष न्यूज

शेयर बाजार में तेजी के दौरान कई कंपनियों के शेयर फोकस में बने हुए हैं। दरअसल इन कंपनियों के शेयरों में शानदार खरीदारी देखने को मिली है। हम आपको इस आर्टिकल में बताने वाले हैं कि आखिर इन शेयरों में क्यों तेजी है और इनका शेयर प्राइस क्या है। आइए इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं।

नई दिल्ली। शेयर बाजार के दोनों सूचकांक तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। बाजार में आई इस तेजी भरे कारोबार में कई शेयर फोकस में बने हुए हैं। हम आपको नीचे उन शेयरों के बारे में बताएंगे जो आज बहुत के साथ कारोबार कर रहे हैं और निवेशकों के फोकस में भी हैं।

निवा बूपा शेयर
इंश्योरेंस (Insurance) सेक्टर की पॉपुलर कंपनी निवा बूपा के शेयर (Niva Bupa Share) आज फोकस में हैं। दरअसल, कंपनी के शेयर में शानदार तेजी देखने को मिली है। 10.50 बजे के करीब कंपनी के शेयर 12.72 फीसदी की बढ़त के साथ 92.35 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार

कर रहे थे।

आपको बता दें कि निवा बूपा के शेयर की लिस्टिंग नवंबर महीने में हुई थी। कंपनी ने हाल ही में घोषणा किया था कि वह लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance) और हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) में शामिल जीएसटी को दूरों को कम करेगी। इस फैसले के बाद कंपनी के शेयर में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी।

एचडीएफसी बैंक शेयर (HDFC Bank Share)

देश के सबसे बड़े बैंक यानी एचडीएफसी बैंक के शेयर भी आज तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के शेयर 10.50 बजे 1.50 फीसदी चढ़कर 1,849.80 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे। माना जा रहा है कि बैंक ने एक ब्लॉक डील की है। इस ब्लॉक डील के बाद बैंक के शेयर में तेजी आई है।

डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड शेयर (Dixon Technologies Share Price)

आज 11.15 बजे डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के शेयर 3 फीसदी की तेजी के साथ 17,385.05 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे। कंपनी की सॉल्यूटिवरी

पीएम आवास योजना का लाभ पाना हुआ आसान, ऑनलाइन आवेदन के लिए फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

सरकार ने सभी के लिए खुद का घर हो इसके लिए वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) शुरू किया था। इस योजना में लाभार्थियों को सरकार की तरफ से घर या फिर घर निर्माण के लिए आर्थिक मदद मिलती है। अगर आप भी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि आप कैसे आवेदन कर सकते हैं।

नई दिल्ली। सबसे पास खुद का आशियाना हो इसके लिए केंद्र सरकार ने साल 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) शुरू की थी। इस योजना में लाभार्थियों को सरकार की तरफ से घर या फिर घर निर्माण के लिए आर्थिक मदद मिलती है। सरकार द्वारा जारी डेटा के अनुसार अभी तक इस योजना का लाभ करोड़ों लोगों को मिला है।

इस योजना की खास बात है कि पीएम आवास योजना का लाभ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में मिलता है। अगर आप भी इस योजना का लाभ पाना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे कि आप इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। वैसे तो इस योजना के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको दफ्तर के चक्कर काटने होंगे। ऐसे में इस परेशानी से बचने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन
स्टेप 1: पीएम आवास योजना के ऑफिशियल वेबसाइट (pmais.gov.in) पर जाएं।

स्टेप 2: अब आपको नागरिक मूल्यांकन (Citizen Assessment) पर क्लिक करना है और स्क्रीन पर शो हो रहे तीन ऑप्शन में से एक को सेलेक्ट करें।

स्टेप 3: इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड (Aadhaar Card) की डिटेल्स को दर्ज करना है और फिर Check पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब आप दूसरे पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां आपको सभी डिटेल्स देनी हैं। याद रखें गलत जानकारी देने पर आपका आवेदन खारिज भी हो सकता है।

स्टेप 5: सभी जानकारी भरने के बाद आपको कैप्चा दर्ज करना और Save को सेलेक्ट करना है।

स्टेप 6: इसके बाद आपको योजना से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और फॉर्म सबमिट करना है।

ये डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी
पहचान पत्र (Identity Proof) के तौर पर आप पैन कार्ड (Pan Card), आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card), ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License Card) अल्पसंख्यक होने पर कास्ट सर्टिफिकेट (Cast Certificate) अपलोड करें

मिनरल वाटर है बेहद खतरनाक, FSSAI के अनुसार पैकेज्ड पानी उच्च जोखिम वाला उत्पाद

परिवहन विशेष न्यूज

हम जो मिनरल वाटर या बोतल बंद पानी पीते हैं वह हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। दरअसल FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) ने इसे उच्च जोखिम वाला उत्पाद की कैटेगरी में रखा है। इसको लेकर FSSAI ने रिपोर्ट जारी किया है। FSSAI ने कहा है कि अब कंपनियों को सालाना निरीक्षण करवाना होगा।

नई दिल्ली। हम जब भी बाहर घूमने या रेस्टोरेंट पर जाते हैं तो अक्सर बोतल वाला पानी या मिनरल वाटर लेना पसंद करते हैं। हमको लगता है कि यह कभी प्योर होता है। अब इसको लेकर एक बड़ी बात सामने आई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने बोतल वाले पानी यानी मिनरल वाटर के नाम पर बिकने वाले को उच्च जोखिम वाली खाद्य श्रेणी (High Risk Food Category) में रखा है। इसका मतलब है कि मिनरल वाटर के नाम पर जो पानी बिक रहा है वो हमारे सेहत के लिए काफी हानिकारक है।

FSSAI ने जारी किया रिपोर्ट

FSSAI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कई उत्पाद भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) प्रमाणन के भीतर नहीं होता है। 'पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर' भी भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तय मापदंड के भीतर नहीं आता है। इस वजह से इसे 'उच्च जोखिम वाले खाद्य श्रेणियों' में शामिल किया गया है। इसके बाद एफएसएसआई ने फैसला लिया है कि मिनरल वाटर का निरीक्षण थर्ड पार्टी के ऑडिट पैरामीटर के अधीन होगा। इसके अलावा FSSAI ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पैकेज्ड



FSSAI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कई उत्पाद भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) प्रमाणन के भीतर नहीं होता है। 'पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर' भी भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तय मापदंड के भीतर नहीं आता है। इस वजह से इसे 'उच्च जोखिम वाले खाद्य श्रेणियों' में शामिल किया गया है। इसके बाद एफएसएसआई ने फैसला लिया है कि मिनरल वाटर का निरीक्षण थर्ड पार्टी के ऑडिट पैरामीटर के अधीन होगा। इसके अलावा FSSAI ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पैकेज्ड

ड्रिंकिंग वाटर को लेकर रेगुलेटर ने रिस्क बेस इस्पेक्शन पॉलिसी में बदलाव किया है।

अब हर साल होगी जांच

FSSAI की रिपोर्ट के बाद अब पैकेज्ड

और मिनरल वाटर निर्माताओं की मुश्किल बढ़ गई है। दरअसल, उन्हें अब रिस्क बेस इस्पेक्शन से गुजरना होगा जो हर साल होगा।

FSSAI ने नवंबर के अंत में एक आदेश जारी

किया था कि जो खाद्य उत्पाद बीआईएस प्रमाणन से हट गए हैं उन्हें लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के लिए हर साल निरीक्षण करवाना होगा।

इसके अलावा जिन प्रोडक्ट को उच्च जोखिम वाले खाद्य श्रेणियों में रखा गया है उन्हें एनुअल ऑडिट करवाना होगा। यह थर्ड पार्टी ऑडिटिंग एजेंसी से आसानी से हो जाएगा। दरअसल, यह फैसला उत्पादों की गुणवत्ता को मापने और उसमें सुधार लाने के लिए लिया गया है। FSSAI ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ड्रिंकिंग वाटर इंडस्ट्री ने सरकार से मांग की थी कि वह नियमों को सरल बनाए। दरअसल, वर्तमान में ड्रिंकिंग वाटर इंडस्ट्री को भारतीय मानक ब्यूरो BIS और FSSAI से प्रमाण लेना होता है।

पीएफ क्लेम के नियमों में बदलाव आधार नहीं इन डॉक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत



परिवहन विशेष न्यूज

ईपीएफओ ने क्लेम के नियमों में बदलाव किया है। अगर आप भी ईपीएफओ में क्लेम करने वाले हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए है। दरअसल ईपीएफओ के नियमों के अनुसार कुछ खास कर्मचारियों को अब क्लेम के लिए आधार कार्ड (Aadhaar Card) का आवश्यकता नहीं है। हम आपको इस आर्टिकल में ईपीएफओ के नए नियम के बारे में विस्तार से बताएंगे।

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के माध्यम से आप एक मोटा फंड तैयार कर सकते हैं। वैसे तो ईपीएफओ स्कीम रिटायरमेंट के बाद में च्योर होती है। लेकिन, कई परिस्थितियों में आप पीएफ फंड से आंशिक निकासी कर सकते हैं।

ईपीएफओ ने क्लेम प्रोसेस के नियमों को बदल दिया है। अब पीएफ क्लेम करने का प्रोसेस आसान हो गया है। जो हां, अब क्लेम करने के लिए आधार (Aadhaar) की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, यह नियमों केवल खास मेंबर के लिए ही बदला है। आइए, जानते हैं कि यह नियम किन मेंबर के लिए बदला है।

इन मेंबरस को होगा लाभ
नए नियमों के अनुसार इसका लाभ उन कर्मचारियों को होगा जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। दरअसल, इन कर्मचारियों को आधार कार्ड के भी आसानी से अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को आधार से लिंक करने की छूट दी है। ईपीएफओ ने रजिस्टर्ड

इंटरनेशनल कर्मचारी को छूट दिया है। यह वह कर्मचारी हैं जो कुछ समय तक भारत में काम करते थे, लेकिन बाद में वह अपने देश चले गए। चूंकि, यह भारतीय नहीं थे इस कारण इनके पास आधार कार्ड (Aadhaar Card) नहीं है। ईपीएफओ के नए नियम के अनुसार विदेश गए पूर्व भारतीय नागरिक जैसे- नेपाल और भूटान के नागरिकों को इस नियम से लाभ होगा।

इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
रजिस्टर्ड इंटरनेशनल कर्मचारी कई डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से पीएफ क्लेम कर सकते हैं। वह वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट - पासपोर्ट, सिटीजन सर्टिफिकेट या कोई ऑफिशियल आईडी प्रूफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पैन कार्ड, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के माध्यम से भी वेरिफिकेशन हो जाएगा। 15 लाख रुपये से ज्यादा के क्लेम के लिए मेंबर को नियोक्ता से भी वेरिफिकेशन करवाना होगा।

क्या है क्लेम का नियम
ईपीएफओ के नए नियमों के अनुसार किसी भी क्लेम रिक्वेस्ट को अधिकारी द्वारा पहले सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी। इसके बाद स्वीकृति अधिकारी-प्रचारी (OIC) के जरिये ई-ऑफिस फाइल को मंजूरी मिलेगी। इस मंजूरी के बाद ही क्लेम का प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा।

ईपीएफओ भी कर्मचारी को सलाह देता है कि वह हमेशा एक ही यूएएन नंबर को रखें। इससे पिछला सर्विस रिकॉर्ड ट्रैक करना और क्लेम मिलने में आसानी होती है।

दिल्ली मेट्रो की सबसे लंबी सुरंग की खोदाई का काम पूरा, दूसरे ट्रैक को लेकर भी आया अपडेट

दिल्ली मेट्रो के फेज चार में बनने वाली सबसे लंबी सुरंग का निर्माण पूरा हो गया है। तुगलकाबाद एयरफोर्स लॉन्चिंग शॉफ्ट और मां आनंदमयी मार्ग के बीच 2.65 किलोमीटर लंबी इस सुरंग को खोदने में TBM अमृत का इस्तेमाल किया गया। यह सुरंग लगभग 16 मीटर की औसत गहराई पर बनाई गई है।

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो के फेज चार के तुगलकाबाद-एरोसिटी कॉरिडोर पर तुगलकाबाद एयरफोर्स लॉन्चिंग शॉफ्ट और मां आनंदमयी मार्ग के बीच 2.65 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग खोदने का काम पूरा हो गया है। दिल्ली मेट्रो की यह सबसे लंबी सुरंग है। इसकी खोदाई के लिए 105 मीटर लंबी टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) 'अमृत' का उपयोग किया गया। इससे इमारतों और अन्य सतही संरचनाओं को नुकसान पहुंचाए बिना सुरंग खोदी जा सकती है। इस कारण यह भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में भूमिगत सुरंग बनाने के काम के लिए उपयोगी है।

आनंदमयी मार्ग साइट पर काम हुआ पूरा

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के निदेशक (परियोजना) राजीव धनखंड और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में बुधवार को आनंदमयी मार्ग साइट पर यह काम पूरा किया गया। एरोसिटी-तुगलकाबाद कॉरिडोर (Aerocity-Tughlaqabad Corridor) के इस खंड पर दो समानांतर गोलाकार सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है।

करीब 16 मीटर की औसत गहराई पर बनाई गई नई सुरंग
दूसरी सुरंग की खोदाई का काम अगले माह



में पूरा होने की उम्मीद है। नई सुरंग लगभग 16 मीटर की औसत गहराई पर बनाई गई है। सुरंग में लगभग 1894 रिंग लगाए गए हैं, जिनका आंतरिक व्यास 5.8 मीटर है।

दिल्ली मेट्रो के फेज चार के तुगलकाबाद-एरोसिटी कॉरिडोर पर सबसे लंबी सुरंग की खोदाई का काम पूरा किया गया।

निर्माण कार्य के दौरान सुरंग के ऊपर के भवनों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचे इसके लिए अत्यधिक संवेदनशील उपकरणों से

जमीन की गतिविधियों पर नजर रखी गई। तुगलकाबाद कॉरिडोर में कुल 19.343 किमी खंड भूमिगत है।

30 टीबीएम के सहयोग से करीब 50 किमी भूमिगत खंड का निर्माण

फेज चार में 40.109 किलोमीटर भूमिगत लाइनों का निर्माण किया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो के फेज चार से ही सुरंग बनाने के लिए एक टीबीएम का उपयोग हो रहा है। फेज तीन में 30 टीबीएम के सहयोग से लगभग 50 किमी

भूमिगत खंड का निर्माण किया गया था। वहीं पर यूपी के साहिबाबाद और न्यू अशोक नगर के बीच दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ RRTS कॉरिडोर (Delhi-Ghaziabad-Meerut RRTS Corridor) पर ट्रायल रन का काम जोरों पर है। आनंदविहार और न्यू अशोक नगर स्टेशनों के जल्द ही खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके चालू होने के बाद RRTS कॉरिडोर की लंबाई 42 किमी से बढ़कर 54 किमी हो जाएगी

सरायकेला में भव्य अन्नपूर्णा मंदिर की प्रतिष्ठा पुरी के पंडितों ने की



कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड झारखंड

सरायकेला ऐतिहासिक शहर में सैकड़ों साल पुरानी अन्नपूर्णा पूजा निमित्त अन्नपूर्णा देवी की भव्य मंदिर निर्माण पश्चात उसका विधिवत प्रतिष्ठा जगन्नाथ धाम पुरी एवं ओडिशा के जाजनागर (जाजपुर) से आये पंडितों ने की। जहां सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने शस्य अंकुरण, कलश यात्रा, सूर्य पूजा, गौ पूजा, चंडी पाठ, यज्ञ आदि का कार्यक्रम में शामिल हुए।

करीब ढाई सौ वर्ष चली आ रही सरायकेला जगन्नाथस का पूजा रहा मां अन्नपूर्णा हेतु

अब प्रभाग संख्या 11 में एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। पहले सड़क पर यह पूजा होती रही। इस मंदिर का प्रतिष्ठा पुरी से आये सुधाकर मिश्र तथा याजपुर के गिरिजा शंकर पांडी ने विधिवत मंत्रोच्चार एवं यज्ञ कर किया। जिसमें उत्कलीय परंपरानुसार सर्वप्रथम सूर्यपूजा, गौ पूजा, चंडीपाठ, सर्वतभद्र मंडल, वास्तु, चुडाकरण, गर्भाधान संस्कार, पीठ पूजा के बाद जो सर्वाधिक

महत्वपूर्ण पूजा हुई उसमें पाताल नरसिंह, अष्ट क्षेत्र पाल, मुसल नृसिंह, उग्र भैरव श्री शुकत संपुटित हवन संपन्न हुआ। देर रात तक प्रसाद वितरण कार्य जारी रहा। इस सामूहिक पूजन में कर्ता के रूप में कार्तिक परिच्छा तथा उनकी धर्मपत्नी बबिता बराल परिच्छा ने पूजन व आहुती कार्यक्रम में बैठे। मंदिर निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले परेश मोहान्ती, शंकर शतपथी, भागिरीश परिच्छा, लिपु मोहान्ती, सीपु मोहान्ती आकाश कर, प्रदीप साहु आदि ने बड़ चढ़कर हिस्सा लिया।

चुनावों का आवश्यक कर्मकांड बना ईवीएम को कोसना

(डॉ. मुकेश "कबीर"-विभूति फीचर्स)

दीवार फिल्म के दो भाईयों की तरह यदि नेताओं के पास, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है तो जनता के पास क्या है? क्या है हमारे पास? तो इसका सॉल्यूशन जवाब है - भाई, मेरे पास ईवीएम है। ईवीएम प्रजातंत्र में बरदादा तो वोट काट को मिला है, जिसमें हम अपनी उंगली के इशारे से देश की दशा और दिशा तय कर सकते हैं लेकिन दिक्कत यह है कि आजकल ईवीएम को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और मजे की बात यह है कि ईवीएम के चरित्र पर लांछन उसी पार्टी के लोग लगा रहे हैं जो इसको देश में लेकर आए। जब भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त टी एन शेखन ने चुनाव प्रक्रिया में सुधार शुरू किया तो वोट कांड और बाद में ईवीएम जनता को मिले। उद्देश्य यही था कि चुनाव में धांधली को रोका जा सके और जनता बाहुबलियों के चंगुल से बाहर आ सके। लेकिन आज इसी ईवीएम पर सबसे ज्यादा उठाए जाते हैं। अब हर चुनाव के बाद ईवीएम को

दोष देना चुनाव का ही एक हिस्सा बन चुका है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा शादी के बाद सास ननद द्वारा दुल्हन में कमियां निकालना जबकि दुल्हन को पसंद भी ये ही लोग करके लाते हैं। अब ईवीएम को कोसना चुनावों का एक आवश्यक कर्मकांड बन चुका है। यदि चुनावों के बाद ईवीएम को दोष न दिया जाए मतलब चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। इस बार महाराष्ट्र चुनाव के बाद भी यह मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया जा रहा है, पहली बार ईवीएम के खिलाफ जनता भी बोल रही है। यही कारण है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि करीब सौ सीटों पर नेताओं ने ईवीएम की जांच के लिए चुनाव आयोग से मांग की है और इसके लिए करीब अड़तालीस लाख रुपए फंड के रूप में जमा भी किए जा चुके हैं और गड़बड़ी पाए जाने पर पुनर्मतदान की मांग भी हो चुकी है। कुछ लोग तो निर्वाचन अधिकारी के अलावा कोर्ट भी जा रहे हैं अब देखते हैं इसका रिजल्ट कब और क्या निकलेगा, इंतजार करें। मुझे लगता है कि इसका

कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा और ईवीएम बेकसूर ही निकलेगी। मुझे इसका तकनीकी पक्ष नहीं मालूम लेकिन पराजित नेताओं के विरोधाभासी बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि ईवीएम बेकसूर है। एक तरफ यह सारे नेता ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष पर चुनाव में पैसा बांटने का आरोप भी लगा रहे हैं और कई नेता वोटर्स को वोट डालने से रोकने का आरोप भी लगा रहे हैं। इसलिए अब सवाल यह उठता है कि यदि ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है तो पैसा बांटने की क्या जरूरत है? और यदि चुनाव में पैसा बांटना जा रहा है या वोटों को वोट देने से रोका जा रहा है इसका मतलब है ईवीएम में गड़बड़ी नहीं की जा सकती, यह विरोधाभासी बयान खुद ही साबित कर देते हैं कि विपक्ष खुद सुनिश्चित नहीं है और दूसरी बात यह है कि यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है इसके पहले भी ईवीएम बेकसूर तक जा चुकी है और कोर्ट से बाइजजत करी भी हो चुकी है इसलिए इस बार भी



बड़ा उलटफेर नहीं होने वाला है लेकिन दिल है कि मानता नहीं इसलिए लोग फिर से पहुंच रहे हैं कोर्ट। अब देखते हैं मीलाड क्या कहते हैं। बहरहाल हम तो ईवीएम के पक्ष में हैं क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। जिस दूसरे विकल्प की मांग विपक्ष लगाता कर रहा है वो है बैलेट पेपर। जिसमें धांधली के चांसेज ज्यादा

होते हैं। पूर्व में हम देख भी चुके हैं कि बैलेट पेपर में बूथ लूट लिए जाते थे, एक ही बंडा पांच सौ छह सौ वोट डाल देता था और पूरा चुनाव डंडे और गुंडे मैनेज कर लेते थे। अंततः राजनीति पर बाहुबलियों का कब्जा हो जाता था लेकिन ईवीएम पर इतनी दादागिरी की संभावना नहीं होती। यही कारण है कि देश में वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है।

खासकर महिलाएं भी अब सुरक्षित रहकर वोट दे सकती हैं इसलिए बैलेट पेपर की वापसी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हां यदि कोई और बेहतर विकल्प हो तो उस पर विचार किया जा सकता है वरना ईवीएम ही ठीक है इस सारे परिदृश्य में आज कम से कम मतदाता कह तो सकता है कि हमारे पास ईवीएम है।"

आधुनिक विकास और गंगा के अस्तित्व पर मंडराता संकट

कुमार कृष्णन-विनायक फीचर्स

भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा जो भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2510 किमी की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भू भाग को सींचती है, देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। 2071 कि.मी तक भारत तथा उसके बाद बांग्लादेश में अपनी लंबी यात्रा करते हुए यह सहायक नदियों के साथ दस लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अति विशाल उपजाऊ मैदान की रचना करती है। सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण गंगा का यह मैदान अपनी घनी जनसंख्या के कारण भी जाना जाता है। 100 फीट (31 मीटर) की अधिकतम गहराई वाली यह नदी भारत में पवित्र मानी जाती है तथा इसकी उपसासना माँ और देवी के रूप में की जाती है। भारतीय पुराण और साहित्य में अपने सौंदर्य और महत्व के कारण बार-बार आदर के साथ चिंतित और नदी के प्रति विदेशी साहित्य में भी प्रशंसा और भावुकतापूर्ण वर्णन किए गए हैं।

वैज्ञानिक मानते हैं कि इस नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं, जो जीवाणुओं व अन्य हानिकारक सूक्ष्मजीवों को जीवित नहीं रहने देते हैं। गंगा की इस असंमित शुद्धिकरण क्षमता और सामाजिक श्रद्धा के बावजूद इसका प्रदूषण रोका नहीं जा सका है। आलम यह है कि इसे रोकने में सरकारी तंत्र का स्वैय्या भी सुस्त है। तभी तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा है कि महाकुंभ मेले में करोड़ों लोग आते हैं, अगर सीवेज के मल-जल को गंगा में गिरने से नहीं रोका गया तो लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होगा।

गंगा बेसिन का लगभग 79 फीसदी क्षेत्र भारत में है। बेसिन में 11 राज्य शामिल हैं, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली। गंगा बेसिन से जुड़े सवालों को लेकर गंगा मुक्ति आंदोलन की ओर से बिहार के मुजफ्फरपुर के चंद्रशेखर भवन, मिठनपुरा में रंग गंगा बेसिन: समस्याएं एवं समाधान विषयक राष्ट्रीय विमर्श में जुटे देश के आठ राज्यों और नेपाल के प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर गंगा के सवाल पर देशव्यापी अभियान चलाने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय विमर्श के केन्द्र में नदियों का गद से पेट भरना, प्रदूषण (औद्योगिक और नगरीय



कचरा) पानी की कमी, बालू उठाव और खनन, नदी की जैव विविधता, ग्लेशियर का पिघलना, जलवायु संकट, कार्बन उत्सर्जन, पारिस्थितिकी असंतुलन, औद्योगिक क्रांति से पनपे विकास की विनाशकारी अवधारणा और जल जंगल जमीन पर जीने वाले समुदाय का अधिकार रहे। कार्यक्रम में आनं लाइन जुड़कर आईआईटी कानपुर के प्रो. डॉ. राजीव सिन्हा, बीबीसी के चर्चित पत्रकार रहे राम दत्त त्रिपाठी, पूर्व सांसद एवं चौथी दुनिया के संपादक संतोष भारतीय, बिहार सरकार में अपर मुख्य सचिव रहे ध्यास जी एवं विजय प्रकाश, उत्तराखंड के नदी कर्मी सुरेश भाई सहित तमाम लोगों की चिंता इस बात को लेकर रही कि आखिर विनाश का खेल कब तक जारी रहेगा। उत्तराखंड के सुरेश भाई का कहना था कि मध्य हिमालय में स्थित गौमुख ग्लेशियर में हो रहे बदलाव को समझना बहुत जरूरी है। समय रहते यदि इसके चारों ओर के पर्यावरण संरक्षण और संयमित विकास पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। उत्तराखंड में गंगा के उद्गम आपदा और जलवायु परिवर्तन के चलते बुरी तरह प्रभावित है। इस भयानक स्थिति के बाद भी गंगा की एक महत्वपूर्ण धारा भागीरथी के उद्गम से ही गंगा की निर्मलता को लेकर एनजीटी ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दूसरी बात है कि भागीरथी के उद्गम में लाखों देवदार के पेड़ों पर संकट की तलवार लटक रही है। यहां चौड़ी सड़क बनाने के लिए घने देवदार के जंगल को काटने की तैयारी चल रही है। इस विषय को तो राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बनाया जाना ही चाहिए और एक बार फिर देशवासी उद्गम से लेकर देश में जहां-जहां से गंगा बह

रही है उन तमाम राज्यों से हो रहे प्रदूषण, अतिक्रमण, शोषण के खिलाफ एक बार फिर से रनदी बचाओ अभियान की तर्ज पर एकत्रित होकर आवाज बुलंद करना चाहिए।

पूर्व सांसद अली अनवर का कहना था कि गंगा का सवाल धार्मिक मामला नहीं है, जिसका राजनीतिक दोहन किया जा रहा है, बल्कि यह सांस्कृतिक मामला है। धार्मिक भावनाओं का शोषण करने के लिए राजनीतिक दल के लोग तरह-तरह की बातें करते हैं। नरामा गंगे योजना के नाम पर पिछले 10 साल से लूट मची है। यह योजना एक तरह से फेल है। पैसे भ्रष्टाचारियों व ठेकेदारों की जेब में जा रहे हैं। यकीनन यह सब गंगा को मारने की योजना है। विकास का विद्रूप चेहरा जो सभ्यता और संस्कृति की पावन धारा में सड़ांध पैदा करने से बाज नहीं आता। इस विकास का लक्ष्य गंगा की पवित्रता और अखिरलता सुनिश्चित करना नहीं है, बल्कि इसकी निगाहें गंगा सफाई के लिए आवर्तित बजट की बंदरबंटा पर ही ज्यादा टिकी है।

गंगा एक संस्कृति का नाम है इसलिए गंगा की लड़ाई संस्कृति बचाने की लड़ाई है। गंगा मुक्ति आंदोलन के संस्थापक अनिल प्रकाश कहते हैं कि गंगा की हत्यारी आधुनिक विकास की नीति है। दिल्ली के पत्रकार प्रसून लतांत कहते हैं कि योजनाएं जब तक जनता की अपेक्षा के प्रतिकूल होंगी तो यही होगा। गंगा या नदी घाटी की सभ्यता को बचाने के प्रयास तभी सार्थक होंगे, जब गंगा पर आश्रित समुदाय से विमर्श कर योजनाएं बनें। मधुपुर झारखंड के पर्यावरणविद सामाजिक कार्यकर्ता धनश्याम जी की चिंता बांधों को लेकर है, उनके अनुसार अमेरिका के केनसी वैली के

तर्ज पर कोलकाता बंदरगाह को साफ करने के लिए दामोदर को बांधा गया, तत्पश्चात फरक्का बराज बनाया गया। फरक्का बराज का विरोध उस वक्त इंजीनियर कपिल भट्टाचार्य ने किया था। गंगा मुक्ति आंदोलन के प्रणेता अनिल प्रकाश ने गंगा समेत अन्य नदियों को दोहन से बचाने के लिए बड़े आंदोलन का आह्वान किया साथ ही कहा कि जब दूसरे देश में बांध तोड़े जा रहे हैं, तब वहीं आज भारत में विश्व बैंक से कर्ज लेकर बांध पर बांध बनने को ही झंडी दी जा रही है। इसके मूल में राजनेता, नौकरशाही और ठेकेदारों का गठजुट है। सारा खेल कमीशन का है। इसके कारण पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्या कारण है कि बांधों के सवाल पर सरकारी कमेटी में शामिल विशेषज्ञों की राय को नजर अंदाज किया जा रहा है।

कार्यक्रम में राजस्थान महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, भागलपुर, कहलगांव एवं नेपाल के दर्जनों ऐसे लोग शामिल हुए, जो पर्यावरण, नदी, जल-जंगल-जमीन को लेकर काम कर रहे हैं। इस मौके पर वीरेंद्र क्रांति वीर, हेमलता महर्षक, अखिलेश कुमार, कृष्ण कुमार मावी, आदित्य सुमन, गणेश, राजा राम सहनी, चंद्रेश्वर राम, बागमती संघर्ष मोर्चा से नवल किशोर सिंह, ठाकुर देवेंद्र, डॉ संतोष सारंग, जगन्नाथ पासवान, राम एकबाल राय, अरविंद, कृष्ण प्रसाद, डॉ नवीन झा, श्याम नारायण यादव, राजीव, शाहिद कमाल ने शिरकत की। साथ ही फैसला लिया गया कि 22 फरवरी 2025 को गंगा मुक्ति आंदोलन के वर्षगांठ पर कागजी टोला कहलगांव, भागलपुर में पुनः देश भर से परिवर्तनवादी जुटेगें और आगे की योजना बनाएंगे। गंगा मुक्ति आंदोलन ने कई मुद्दों के साथ बिहार को नदियों में फ्री फिशिंग एक्ट बनाने के आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया है। 1990 में बिहार सरकार ने पारंपरिक मछुआरों को नदी में निःशुल्क मछली पकड़ने का अधिकार दिया था, जिसे छल और फरेब से अब शिथिल किया जा रहा है। बिहार में अभी स्पेशल जमीन सर्वे भी चल रहा है। नदियों की जमीन का सीमांकन (चौहद्दी) और रकबा निर्धारित करने को लेकर अभियान चलाने की बात कही गयी। इसके साथ ही संकल्प लिया गया कि गंगा की अखिरलता और निर्मलता बहाली के लिए गंगा के स्वाभाविक निदान के लिए फरक्का बराज को खोलने सहित सभी बांध बराज तटबंध को खत्म कर नदियों की प्राकृतिक अवस्था बहाल करने और किसी भी प्रकार का प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न करने के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा।

आज भारतीय नौसेना दिवस है, पुरी से दुनिया देखेगी नौसेना की ताकत

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओडिशा

पुरी/भुवनेश्वर: हर साल 4 दिसंबर को उन वास्तविक नायकों को सम्मानित करने के लिए भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है जो जलमार्ग में दुश्मन को चकमा देते हैं। यह दिन पूरे देश में

बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कराची पर हुए हमले की याद में नौसेना आज का दिन मना रही है। यह भारतीय नौसेना बलों को सम्मानित करने और उनके योगदान की सराहना करने का एक विशेष दिन है। नौसेना दिवस के मौके पर आज पुरी ब्लूप्लैग बीच पर खास जयन मनाया जाएगा। पुरी से पुरी दुनिया नौसेना की ताकत देखेगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। इस महान दिन के मनाए जाने के कारण समुद्र तट पर नौसेना की ताकत देखने के लिए लोगों में भारी उत्साह होता है। नौसेना एक सप्ताह से रिहर्सल कर रही थी। इस भव्य आयोजन में राष्ट्रपति समेत 7500 आमंत्रित अतिथि शामिल होंगे। लगभग 4 टैंक, 15 युद्धपोत, 30 युद्ध हेलीकॉप्टर, 5 युद्ध विमान और 5 जेट पुरी समुद्र और समुद्र तट पर युद्ध रणनीति का प्रदर्शन करेंगे। नौबरी पुरी के आसमान में दिखाएंगे शक्ति!

पुरी में नौसेना दिवस पर विशेष कार्यक्रम, राष्ट्रपति ने किया उद्घाटन



मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओडिशा

पुरी/भुवनेश्वर: भारतीय नौसेना दिवस है। भारतीय नौसेना की ताकत पुरी दुनिया देखेगी। पुरी के समुद्र तट पर नौसेना का युद्धाभ्यास किया जाएगा। आकर्षक परेड पुरी के समुद्र तट को अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली कला से हिला देगी। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति समेत जानी-मानी हस्तियां शामिल हुई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्लूप्लैग बीच पर पहुंचीं। राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नौसेना दिवस समारोह का उद्घाटन किया।